समक्ष ए. बी. सहारिया, सी. जे. और स्वतंत्र कुमार, जे.

भारत संघ,-याचिकाकर्ता

बनाम

मेसर्स हरबंस सिंह तुली और बेटे,-प्रतिवादी

1994 का सी. आर. सं. 1685

31 सेंट जनवरी, 2000

मध्यस्थता अधिनियम, *1940*-एस. धारा *2 (*सी*), 4,5,8,11,12,14,20,28* और *31*-यू. ओ. आई. और एक ठेकेदार के बीच अनुबंध समझौता-पक्षों के बीच विवाद-नामित प्राधिकारी द्वारा नियुक्त मध्यस्थों ने या तो इस्तीफा दे दिया या कार्य करने में विफल रहे-ठेकेदार के दावे पर निर्णय नहीं लिया जा सका-नोटिस के बावजूद, सरकार एक मध्यस्थ नियुक्त करने में विफल रही-ट्रायल कोर्ट ने एक मध्यस्थ की नियुक्ति की और बाद में पिछले मध्यस्थ को हटाकर दूसरे मध्यस्थ की नियुक्ति का आदेश दिया।

मध्यस्थ-नियुक्ति के आदेश को चुनौती देने वाला भारतीय संघ.-ट्रायल कोर्ट के आदेशों ने अंतिमता प्राप्त की-अधिनियम की धारा *8* के तहत एक मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए ट्रायल कोर्ट का अधिकार क्षेत्र-का दायरा, ट्रायल कोर्ट द्वारा प्रारंभिक नियुक्ति को स्वीकार करने के बाद, यू. ओ. आई. को रखरखाव के आरोप पर ट्रायल कोर्ट द्वारा बाद की नियुक्तियों को चुनौती देने के लिए हटा दिया जाएगा-सुने जाने का अधिकार भारतीय संघ अपने एकमात्र मालिक की मृत्यु के बाद कंपनी के सुने जाने के अधिकार के संबंध में आपत्ति उठाने में विफल रहा-कंपनी के रुख को विशेष रूप से स्वीकार करने और खुद को एकमात्र प्रतिवादी के रूप में कंपनी को शामिल करने के बाद, यू. ओ. आई. कंपनी के लोकस स्टैंडी के संबंध में *17* साल बाद आपत्ति नहीं उठा सकता है।

अभिनिर्धारित किया कि मध्यस्थ की नियुक्ति न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना और समझौते के खंड 70 के तहत निर्धारित तंत्र के तहत पक्षों की सहमति पर तीन अलग-अलग अवसरों पर नामित प्राधिकारी द्वारा की गई थी।इसके बाद, न्यायालय द्वारा मध्यस्थों की नियुक्ति की गई, जिन्हें पक्षकारों ने स्वेच्छा से स्वीकार किया या ऐसे आदेशों को कानून में या अन्यथा अंतिमता प्राप्त हुई। विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजने के लिए पक्षों के बीच एक समझौता हुआ था।एक नियुक्त मध्यस्थ था।मध्यस्थों ने उपेक्षा की थी या इनकार कर दिया था या अपने इस्तीफे के कारण या अन्यथा अक्षम हो गए थे।समझौते से यह नहीं पता चलता है कि पार्टियों का रिक्ति की आपूर्ति करने का इरादा नहीं था और रिक्ति वास्तव में सूचना के बाद प्रदान नहीं की गई थी।वर्तमान मामले में शर्तों को पूरा करने के कारण हम न्यायालय द्वारा एक स्वतंत्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवेदन की स्थिरता के संबंध में भारत संघ की आपत्ति के आधार को समझने में असमर्थ हैं। वर्तमान मामला प्रारंभिक नियुक्ति का नहीं है, बल्कि स्वयं न्यायालय द्वारा नियुक्त किए जाने वाले क्रमिक मध्यस्थों का है।नोटिस के प्रावधानों का पालन न करने से निश्चित रूप से सक्षम न्यायालय द्वारा अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए नामित प्राधिकारी द्वारा अपने अधिकार का त्याग करने और प्रतिबंध, यदि कोई हो, को हटाने का प्रभाव पड़ेगा।यह भी स्पष्ट है कि पहले नियुक्त किए गए विभिन्न मध्यस्थों ने मध्यस्थ द्वारा इस्तीफे के रूप में कार्य करने से भी इनकार कर दिया था, जो मामले को आगे नहीं बढ़ाने के उसके इरादे की अभिव्यक्ति होगी।जहाँ न्यायालय इन घटकों से संतुष्ट है, वहाँ न्यायालय के लिए ऐसी रिक्ति की आपूर्ति करने के लिए कोई बाधा नहीं होगी।

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि मध्यस्थता कार्यवाही में पक्षों का आचरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है जिस पर न्यायालय द्वारा विचार किया जाना चाहिए।न्यायालय द्वारा क्रमिक मध्यस्थों की नियुक्ति की गई हो, जिसे पक्षकारों ने स्वेच्छा से स्वीकार किया हो या उक्त आदेशों को बहुत पहले अंतिमता प्राप्त हो गई हो, मध्यस्थ के समक्ष पक्षकारों की भागीदारी के साथ, आवेदन की स्थिरता या अन्यथा न्यायालय द्वारा ऐसे मध्यस्थों की नियुक्ति पर याचिका के संबंध में पूर्ण छूट के रूप में कार्य करेगा।

(पैरा 43)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि हम श्री गुप्ता को एक मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने में विद्वत विचारण न्यायालय के आदेश में अधिकार क्षेत्र की कोई त्रुटि देखने में असमर्थ हैं, अधिनियम की धारा 11 के तहत निर्धारित आधारों को विशेष रूप से मध्यस्थ को हटाने के लिए अनुरोध किया गया था क्योंकि वह संदर्भ के साथ प्रवेश करने और आगे बढ़ने और एक पुरस्कार देने में सभी प्रतिदनीय प्रेषण का उपयोग करने में विफल रहा।मध्यस्थ इस अधिनियम के तहत इतने शक्तिहीन नहीं हैं कि विवाद का कोई भी पक्ष मध्यस्थ द्वारा संदर्भ के उद्देश्य और इसके निर्धारण को विफल कर सकता है।हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई संकोच नहीं है कि वैकल्पिक रूप से आवेदन को अधिनियम की धारा 11 के तहत एक आवेदन के रूप में माना जा सकता है और न्यायालय के मध्यस्थ की नियुक्ति का परिणामी आदेश कानून के चार कोनों और अधिनियम की धारा 12 के तहत प्रदान की गई इसकी अधिकारिता के भीतर पारित किया गया था। इसलिए, अधिनियम की धारा 8 के तहत आवेदन बनाए रखने योग्य था, भारत संघ ने अपने आचरण द्वारा या अन्यथा अपनी रखरखाव और नियुक्ति पर आपत्ति को माफ कर दिया, यदि कोई हो, और किसी भी स्थिति में आवेदन को अधिनियम की धारा 11 के तहत एक आवेदन के रूप में माना जा सकता है।

(पैरा 50 &51)

इसके अतिरिक्त, यह अभिनिर्धारित किया गया कि जून, 1982 में श्री तुली की मृत्यु के बाद विभिन्न कार्यवाहियां हुईं जिनमें भारत संघ ने स्वयं कंपनी के अधिकार को स्वीकार किया है और कार्यवाहियों में एकमात्र प्रतिवादी के रूप में कंपनी को स्वयं ही दोषी ठहराया है।भारत संघ कंपनी के अधिकार क्षेत्र के संबंध में आपत्ति उठाने में विफल रहा और दूसरी ओर इस पूरी अवधि के लिए कंपनी के रुख को विशेष रूप से स्वीकार करने के बाद, अदालत के लिए भी चीजों को अस्थिर करना अनुचित होगा ताकि वे इस दृष्टिकोण पर 30 साल पहले लौट आएं।

(पैरास 53 &56)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि आम तौर पर सभी कार्यवाहियों को उस न्यायालय में लिया जाना चाहिए जिसने शुरू में मध्यस्थ की नियुक्ति की थी या प्रारंभिक चरण में संदर्भ के विषय से निपटा था।समय के विस्तार के साथ-साथ पुरस्कार और नियंत्रण दाखिल करने के संबंध में बाद के आवेदन

मध्यस्थता कार्यवाहियों को उस न्यायालय में दायर किया जाना चाहिए और बनाए रखा जाना चाहिए जिसके समक्ष शुरू में मध्यस्थता समझौते और संदर्भ के विषय के संबंध में कार्यवाहियां शुरू की गई थीं।संदर्भ की विषय वस्तु पर विचार करने के लिए सक्षम न्यायालय वह न्यायालय होगा जिसे धारा 2 (सी) के तहत परिभाषित किया गया है, एक सिविल न्यायालय जो संदर्भ की विषय वस्तु पर अधिकार क्षेत्र रखता है, यदि वही वाद का विषय था।दूसरे शब्दों में, धारा 31 'न्यायालय' की उप-धारा (4) के तहत सिविल न्यायालय होगा जो अधिनियम के तहत मध्यस्थता कार्यवाही में संदर्भ विषय की प्रकृति के मुकदमे का परीक्षण करने के लिए अधिकार क्षेत्र और सक्षम होगा।

(पैरा 61)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि किसी भी समय उच्च न्यायालय ने अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करते हुए कभी भी किसी मध्यस्थ की नियुक्ति नहीं की थी या

मध्यस्थता कार्यवाही को आगे बढ़ाने में प्रगति के संबंध में भौतिक परिणाम का प्रभावी निर्देश नहीं दिया था।इसके विपरीत, उच्च न्यायालय ने समय-समय पर केवल विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की थी और अभिलेख स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विचारण न्यायालय ने कार्यवाही पर प्रभावी और पूर्ण नियंत्रण का प्रयोग किया था।

(पैरा 86)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि सक्षम अधिकार क्षेत्र का न्यायालय होने के कारण विचारण न्यायालय ने मध्यस्थों की नियुक्ति की थी।इसके अलावा, इन कार्यवाहियों में से किसी भी पक्ष को कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा यदि विद्वत विचारण न्यायालय को मूल अधिकार क्षेत्र का न्यायालय होने के नाते कानून के अनुसार मामलों पर नियंत्रण रखने और उनसे निपटने की अनुमति दी जाती है।

(पैरा 91)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि विद्वत विचारण न्यायालय सक्षम अधिकार क्षेत्र का न्यायालय होने के कारण, निर्णय विचारण न्यायालय के समक्ष दायर किया जाना चाहिए था, जिसने शुरू में श्री गुप्ता को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया था।अधिनियम की धारा 5 और 11 के तहत भारत संघ की याचिका और न्यायालय के पुरस्कार नियम बनाने के लिए दायर की गई उसकी आपत्तियों की सुनवाई और निर्णय विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा एक साथ किया जाएगा।

(पैरा 99)

अरुण नेहरा, सुश्री दीपाली पुरी के साथ अधिवक्ता, यू. ओ. आई. के अधिवक्ता हरकिशन सिंह तुली, व्यक्तिगत रूप से।

1994 का सिविल संशोधन सं. 1685 भारत संघ बनाम एच. एस. तुली एंड संस।

1996 का सिविल संशोधन सं. 1076, एच. एस. तुली एंड संस बनाम भारत संघ।

निर्णय

स्वतंत्र कुमार, जे.

(1) भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 12 अगस्त, 1997 के आदेश के माध्यम से 1996 की विशेष अनुमति याचिका संख्या 18521,18522,18897 और 18898 का निपटारा किया।आदेश इस प्रकार है:—

> "हमने दोनों पक्षों को सुना है।हमारा विचार है कि इस न्यायालय में उठाई गई आपत्तियों की सुनवाई उच्च न्यायालय द्वारा ही की जानी चाहिए।मामले के महत्व को ध्यान में रखते हुए, हम निर्देश देते हैं कि मुख्य न्यायाधीश को स्वयं एक खंड पीठ में बैठकर मामले की सुनवाई करनी चाहिए।मामले की सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ उच्च न्यायालय की किसी अन्य पीठ द्वारा इस मामले में पारित किसी भी पिछले आदेश से बाध्य नहीं होगी।
>
> विशेष अनुमति याचिकाओं का निपटारा किया जाता है।"

(हमारे द्वारा प्रदान किया)

(2) चूँकि भारत संघ की ओर से उपस्थित विद्वान वकील और याचिकाकर्ता द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश, दिनांक 12 अगस्त, 1997 के दायरे के संबंध में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के कारण हमारे सामने कुछ विवाद उठाया गया था, हम यह समझाना अनिवार्य मानते हैं कि हम उक्त आदेश के बारे में क्या समझते हैं।माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में निहित निर्देश के लिए उच्च न्यायालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उठाई गई आपत्तियों को सुने और उच्च न्यायालय की किसी अन्य पीठ द्वारा इस मामले में पारित किसी भी पिछले आदेश से बाध्य न हो।"इस मामले में" अभिव्यक्ति का स्पष्ट रूप से अर्थ है उच्च न्यायालय के समक्ष मामले/आवेदन, जिसके परिणामस्वरूप सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पूर्व-निर्दिष्ट विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की गई थीं।निश्चित रूप से आदेश में दिखाई देने वाली अभिव्यक्ति "इस मामले" का अर्थ यह नहीं है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय सहित सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय द्वारा अन्य संबंधित मामलों में पारित आदेश, जो पहले से ही अंतिमता प्राप्त कर चुके हैं।विचारण न्यायालय के ऐसे आदेश हैं जिन्हें पक्षकारों द्वारा वर्षों से स्वीकार किया गया है और उन पर कार्रवाई की गई है और हमें नहीं लगता कि उच्चतम न्यायालय के उनके अधिपत्य का उद्देश्य उन आदेशों को छोड़कर, जो उच्चतम न्यायालय के समक्ष उपर्युक्त चार विशेष अनुमति याचिकाओं के विषय थे, तय या निर्धारित अधिकारों को अस्थिर करना था।अधिक से अधिक, इस पीठ को उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विभिन्न चरणों या मामलों के अंतिम चरण में पारित आदेशों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, जिन्होंने उक्त चार विशेष अनुमति याचिकाओं को जन्म दिया।इस प्रकार, हम भारत संघ के विद्वान वकील के इस तर्क को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हैं कि पक्षों के बीच पिछली कार्यवाही में सर्वोच्च न्यायालय सहित किसी भी न्यायालय द्वारा पारित सभी आदेशों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए।

(3) मामले को स्पष्ट करने के लिए, शुरुआत में, हम उन मामलों और आवेदनों का उल्लेख करेंगे जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष 4 विशेष अनुमति याचिकाओं को जन्म दिया था।

(4) (क) 1994 के सिविल संशोधन सं. 1685 को भारत संघ द्वारा 4 जुलाई, 1995 के आदेश के खिलाफ पेश किया गया था, जिसे श्री गुप्ता को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने वाले विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित किया गया था।इस संशोधन को इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने 4 जुलाई, 1995 को खारिज कर दिया था।

(5) भारत संघ द्वारा 4 जुलाई, 1995 के आदेश को वापस लेने और उसकी समीक्षा करने के लिए एक समीक्षा याचिका दायर की गई थी।इसे भी उसी माननीय न्यायाधीश ने 7 सितंबर, 1995 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया था।इन दोनों आदेशों को भारत संघ द्वारा 1996 की विशेष अनुमति याचिका संख्या 18521 और 18522 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी।

(6) (ख) 1994 के उक्त सिविल संशोधन सं. 1685 में, मैसर्स हरबंस सिंह तुली द्वारा दो आवेदन दायर किए गए थे और उनके बेटे सिविल माइस थे।1995 का सं. 13460-सी-II और सिविल माइस।1996 का सं. 7375-सी/II।ये आवेदन मध्यस्थ श्री गुप्ता के समक्ष समय बढ़ाने के लिए दायर किए गए थे।इन दोनों आवेदनों को उच्च न्यायालय द्वारा क्रमशः 14 मार्च, 1996 और 16 जुलाई, 1996 के अपने आदेशों के अनुसार अनुमति दी गई थी।इन दोनों आदेशों को भारत संघ द्वारा 1996 की विशेष अनुमति याचिका संख्या 18897 और 18898 में चुनौती दी गई थी।

(7) इस तरह 12 अगस्त, 1997 के एक सामान्य आदेश द्वारा सभी चार विशेष अनुमति याचिकाओं का निपटारा किया गया।

(8) इससे पहले कि हम अपने समक्ष उपस्थित होने वाले पक्षों के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर चर्चा करने के लिए आगे बढ़ें, कुछ बुनियादी तथ्यों का संदर्भ आवश्यक होगा।

(9) पक्षों ने एक समझौता किया था और समझौते के अनुसार, निविदा के नियमों और शर्तों को समझौते का अभिन्न अंग माना जाना था।दोनों पक्षों के बीच समझौते को 19 अप्रैल, 1969 को लागू किया गया था।अनुबंध के तहत काम 2 अगस्त, 1970 तक पूरा किया जाना था।हालांकि, इसे पूरा करने का समय बढ़ा दिया गया था।भारत संघ की ओर से कार्य कर रहे मुख्य अभियंता ने 8 अगस्त, 1973 को अनुबंध रद्द कर दिया।दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया है।ठेकेदार ने 26 सितंबर, 1973 को मध्यस्थता अधिनियम की धारा 20 के तहत एक आवेदन दायर किया था।अनुबंध के खंड 70 के संदर्भ में नामित प्राधिकारी ने कर्नल गुरदियाल सिंह को 24 दिसंबर, 1973 को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया।इस प्रकार, ठेकेदार का आवेदन 15 जनवरी, 1974 को विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था क्योंकि यह निष्फल हो गया था।

ठेकेदार ने तब भी उस आदेश के खिलाफ अपील की जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था।

(10) नामित प्राधिकारी द्वारा एक के बाद एक मध्यस्थों की नियुक्ति की गई और 8 मई, 1984 को प्राधिकरण द्वारा 5 वें मध्यस्थ की नियुक्ति की गई, जिसके समक्ष कुछ कार्यवाही आगे बढ़ी, लेकिन कुछ भी प्रभावी नहीं हो सका क्योंकि ठेकेदार फर्म के एकमात्र मालिक श्री हरबंस सिंह तुली की 16 जून, 1982 को मृत्यु हो गई, जिसमें दावेदार कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री हरकिशन सिंह तुली सहित छह कानूनी प्रतिनिधि पीछे रह गए।8 मार्च, 1988 को श्री पी. डी. गुजराती ने इस्तीफा दे दिया।24 मार्च, 1988 को श्री तुली को दावेदार कंपनी की ओर से मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए नोटिस दिया।दावेदार कंपनी ने दो आवेदन दायर किए-एक 27 फरवरी, 1989 को और दूसरा 17 अक्टूबर, 1989 को।इन दोनों आवेदनों पर विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अंतिम रूप दिया गया।ब्रिगेडियर की नियुक्ति।परिहार को भारत संघ द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष बिल्कुल भी चुनौती नहीं दी गई थी, जबकि श्री वाधवा की नियुक्ति को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी।

(11) निचली अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनाक 9 जुलाई 1993 के माधयम द्वारा 1991 के सिविल संशोधन संख्या 1220 में पारित आदेशों के संदर्भ में बरकरार रखा था। 1991 के सिविल संशोधन सं. 1220 में आदेश को उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी और 1994 के अपील करने के लिए विशेष अनुमति सं. 1139 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 14 जुलाई 1994 को खारिज कर दिया गया था। जल्द ही सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय के प्रश्न पर चर्चा करते हुए इस आवेदन के प्रभाव और उस पर पारित आदेशों पर बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे।

(12) यह दावेदार कंपनी द्वारा 26 अक्टूबर, 1993 को दायर किया गया तीसरा आवेदन था, जिसे विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई थी और श्री ओ. पी. गुप्ता को 5 अप्रैल, 1994 के आदेश के अनुसार मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया था।यह वही आदेश है जिसका वर्तमान संशोधन में उल्लेख किया गया है।

(13) हमें मध्यस्थता खंड अर्थात समझौते की सामान्य शर्त संख्या 70 का उल्लेख करना चाहिए, जो पक्षों द्वारा उठाई गई विवादास्पद याचिकाओं का आधार है, जो निम्नानुसार हैः—

> "70. प्रत्यर्पण-अनुबंध के पक्षों के बीच सभी विवाद (उन लोगों के अलावा जिनके लिए सी. डब्ल्यू. ई. या किसी अन्य व्यक्ति का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होने के लिए व्यक्त किए गए अनुबंध द्वारा किया गया है), दोनों पक्षों में से किसी एक द्वारा लिखित सूचना के बाद निविदा दस्तावेजों में उल्लिखित प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किए जाने वाले इंजीनियर अधिकारी के एकमात्र मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाएगा।
>
> जब तक पक्ष अन्यथा सहमत नहीं होते हैं, तब तक इस तरह का संदर्भ पूरा होने, कार्यों के कथित रूप से पूरा होने या छोड़ने या अनुबंध के निर्धारण के बाद तक नहीं होगा।-
>
> यदि इस प्रकार नियुक्त मध्यस्थ अपनी नियुक्ति से इस्तीफा दे देता है या अपना पद खाली कर देता है या किसी भी कारण से कार्य करने में असमर्थ या अनिच्छुक है, तो उसे नियुक्त करने वाला प्राधिकारी उसके स्थान पर कार्य करने के लिए एक नया मध्यस्थ नियुक्त कर सकता है।
>
> ऐसा माना जाएगा कि मध्यस्थ ने सुनवाई की तारीख तय करते हुए दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने की तारीख को संदर्भ दर्ज किया है।
>
> मध्यस्थ समय-समय पर पक्षों की सहमति से पुरस्कार बनाने और प्रकाशित करने के लिए समय बढ़ा सकता है।

मध्यस्थ उसे निर्दिष्ट किए गए सभी मामलों पर अपना निर्णय देगा और विवाद की प्रत्येक व्यक्तिगत वस्तु पर अलग-अलग दिए गए धनराशियों के साथ अपने निष्कर्षों का संकेत देगा।

मध्यस्थता का स्थान ऐसा स्थान या स्थान होंगे जो मध्यस्थ द्वारा अपने विवेकाधिकार पर तय किया जाए।

मध्यस्थ का पंचॉट अनुबंध के दोनों पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।

(14) दावेदार कंपनी श्री बी. के. वाधवा के कारण हुई रिक्ति की आपूर्ति के लिए तीसरे आवेदन को स्वीकार करती है।उक्त आवेदन में यह दलील दी गई थी कि न्यायालय द्वारा पहले दो मध्यस्थों की नियुक्ति की गई थी और संबंधित प्राधिकारी को नोटिस की सेवा के बाद मध्यस्थ नियुक्त करने में विफल रहने के कारण मध्यस्थ नियुक्त करने की शक्तियों का त्याग कर दिया था।यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि भारत संघ ने सुने जाने के अधिकार के आधार पर इस आवेदन की रखरखाव पर कोई आपत्ति नहीं जताई और अनुरोध किया कि अभियंता को एक मध्यस्थ नियुक्त करना चाहिए। विद्वत विचारण न्यायालय ने मामले के गुण-दोषों पर विस्तार से चर्चा की और निम्नानुसार निर्णय दिया:—

"यह विवादित तथ्य नहीं है कि अनुबंध समझौते के अनुसार, पक्षों के बीच किसी भी विवाद के कारण, एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति मुख्य अभियंता द्वारा की जानी थी, लेकिन जब प्रतिवादी ने नियुक्ति के मामले में पंद्रह साल से अधिक की देरी की, तो याचिकाकर्ता ने एक स्वतंत्र मध्यस्थक के लिए आवेदन किया और श्री ए. के. सूरी,. इस न्यायालय के पूर्ववर्ती ने श्री बी.के.वाधवा को पक्षों के बीच विवाद का निर्णय के लिये दिनाक 16 फ़रवरी1991 के आदेश के अनुसार मध्यस्त नियुक्त किया। 16 फरवरी, 1991 के आदेश से व्यथित प्रतिवादी ने चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय में 1991 का सिविल पुनरीक्षण संख्या 1221 दायर किया और उक्त सिविल पुनरीक्षण में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति श्री वी. के. बाली ने 13 अक्टूबर, *1992* के अपने आदेश के माध्यम से इस अदालत द्वारा 16 फरवरी, 1991 को पारित आदेश की पुष्टि की।माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का कार्यात्मक भाग इस प्रकार है:—

"यह मामले के अभिलेख पर साबित हो चुका है कि भारत संघ द्वारा समय-समय पर नियुक्त मध्यस्थ ने कोई पंचॉट नहीं दिया और इस प्रक्रिया में पंद्रह साल बीत चुके थे।हालाँकि, नीचे दिए गए प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदन के लंबित रहने के दौरान, मध्यस्थ की नियुक्ति भारत संघ द्वारा की गई थी, लेकिन मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, निचली अदालत ने उचित रूप से मध्यस्थ 'श्री बी. के. वाधवा' को नियुक्त किया।"

"साविकृत श्री बी. के. वाधवा ने इस्तीफा दे दिया है।इसलिए, इन परिस्थितियों में, यह न्यायालय में प्रत्यर्थी द्वारा उठाई गई आपत्ति में कोई गुण नहीं है कि एकमात्र मध्यस्थ को मुख्य अभियंत द्वारा नियुक्त किया जाना है जैसा कि अनुबंध समझौते में परिकल्पना की गई है।इस प्रश्न का निर्णय इस न्यायालय द्वारा पहले ही6 फ़रवरी 1991 के आदेश के माधयम से किया जा चुका है- और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश को 13 अक्तूबर 1992 के आदेश के माध्यम से बरकरार रखा गया है और यदि यह न्यायालय फिर से इस प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए समय निकालता है, तो यह याचिकाकर्ता के लिए बहुत पूर्वाग्रह पैदा करेगा, जिसके दावे पर पंद्रह साल से अधिक समय का लाभ उठाने के बावजूद विभिन्न मध्यस्थों द्वारा निर्णय नहीं लिया गया है।दलीलों के दौरान, याचिकाकर्ता ने मध्यस्थ का एक पैनल दायर किया।एक एस. बी. एस. चीमा, एस. ई., पंजाब मंडी बोर्ड, द्वितीय एस. पुरनजीत सिंह, मुख्य अभियंता, चंडीगढ़ आवास बोर्ड, सेक्टर 9,

चंडीगढ़ और श्री ओ. पी. गुप्ता, मुख्य अभियंता, एम. आई. टी. सी., हरियाणा, चंडीगढ़ और प्रत्यर्थी ने अपने जवाब में मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए तीन नामों का भी उल्लेख किया लेकिन उन्हें प्रत्यर्थी के अधीनस्थ नहीं माना जा सकता है।उन्होंने स्वतंत्र मध्यस्थ के किसी पैनल की आपूर्ति नहीं की है।अतः श्री. ओ. पी. गुप्ता, मुख्य अभियंता, हरियाणा, चंडीगढ़ को अनुबंध समझौता सं. CENWZ/AMB-24/1969-70 संदर्भ में प्रवेश करने की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं। फाइल को अभिलेख कक्ष में भेजा जाए।"

(15) इस आदेश की वैधता और पक्षों की ओर से उठाए गए संबंधित तर्कों के लिए, निम्नलिखित प्रश्न न्यायालय के विचार के लिए आते हैं:—

(i) क्या अधिनियम की धारा 4 के साथ पठित समझौते के खंड 70 में मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अधिनियम की धारा 8 के तहत आवेदन, जो एक नामित व्यक्ति द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति को अभिनिर्धारित करता है, बनाए रखने योग्य है?

(ii) क्या भारत संघ विबंधित है और/या उसने अपने आचरण द्वारा आवेदन की रखरखाव पर आपत्ति लेने के अपने अधिकार को माफ कर दिया था या अन्यथा?

(iii) वैकल्पिक रूप से, क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में न्यायालय द्वारा की गई नियुक्ति को अधिनियम की धारा 11 और 12 के दायरे में नियुक्ति कहा जा सकता है?

(16) संघ के विद्वान वकील ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ इस न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों के निर्णयों पर भरोसा करते हुए जोरदार तर्क दिया कि श्री बी. के. वाधवा द्वारा की गई रिक्ति की आपूर्ति और धारा 8 के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए दावेदार कंपनी की ओर से 26 अक्टूबर, 1993 को दायर किया गया तीसरा आवेदन विचारणीय नहीं था।यह तर्क दिया गया था कि एक मध्यस्थ की नियुक्ति का अधिकार क्षेत्र अधिनियम की धारा 4 के दायरे में अकेले नामित प्राधिकारी में निहित है। इस प्रकार, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, न्यायालय ने श्री ओ. पी. गुप्ता को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने में अधिकार क्षेत्र के बिना काम किया है।श्री तुली का तर्क है कि निचली अदालत ने कानून के तय किए गए सिद्धांतों के अनुरूप अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया है और नामित प्राधिकारी ने अपने स्वयं के आचरण और अन्यथा से मध्यस्थ नियुक्त करने का अपना अधिकार खो दिया है।इस उद्देश्य के लिए, उन्होंने भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न निर्णयों पर भी भरोसा किया।हम जल्द ही अपने समक्ष संबंधित पक्षों द्वारा उद्धृत विभिन्न निर्णयों पर चर्चा करने के लिए आगे बढ़ेंगे।

(17) रिकॉर्ड से जो निर्विवाद तथ्य सामने आता है वह यह है कि श्री ओ. पी. गुप्ता की नियुक्ति से पहले दो अलग-अलग आवेदनों पर अदालत द्वारा दो मध्यस्थों की नियुक्ति की गई थी, जबकि पहले आवेदन के तहत अदालत से श्री पी. डी. गुजराती के स्थान पर एक मध्यस्थ नियुक्त करने का अनुरोध किया गया था, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था और 24 मार्च, 1988 के नोटिस के बावजूद इंजीनियर-इन-चीफ रिक्ति प्रदान करने में विफल रहे थे।इस आवेदन की अनुमति दी गई थी। ब्रिग को हटाने के लिए प्रार्थना करते हुए बाद में आवेदन दायर किया गया था।एम. एम. एस. परिहार जिन्होंने दावों का न्यायनिर्णयन और मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए उपेक्षा की थी। इस आवेदन को विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा भी अनुमति दी गई थी और जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है कि इन आदेशों ने अंतिमता प्राप्त कर ली थी और पक्षों ने इन आदेशों पर कार्रवाई की, बिना किसी आपत्ति और विरोध के मध्यस्थता कार्यवाही में भाग लिया।

(18) एक बार अदालत ने ब्रिगेडियर परिहार की नियुक्ति की थी।नामित प्राधिकारी द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन करने में विफल रहने और उन्हें हटाने के लिए बाद में आवेदन दायर करने और खारिज किए जाने के बाद मध्यस्थ के रूप में परिहार के लिए अधिनियम की धारा 8 के दायरे और दायरे में न्यायशास्त्र का प्रयोग करने के लिए शायद ही कोई बाधा हो सकती है। ऐसी याचिका नियुक्ति के प्रारंभिक चरण में भारत संघ के लिए उपलब्ध हो सकती है, लेकिन उसके बाद, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 के तहत शक्तियों का प्रयोग, आवेदक द्वारा इसके अवयवों को संतुष्ट करने पर, उक्त प्रावधानों को पढ़ने का कोई औचित्य नहीं हो सकता है ताकि समझौते के खंड 70 के बावजूद मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए न्यायालय के न्यायशास्त्र को बाहर रखा जा सके।

(19) भारत संघ के विद्वान वकील ने भारत संघ, बनाम एम/एस अजीफ, मेहता एंड एसोसिएट्स, पुणे और अन्य *(1)* और बृज भूषण लाल बनाम मुख्य अभियंता, उत्तर पश्चिमी स्लोन

*(*केंद्र सरकार*)* और एक अन्य *(2)* पर भारी निर्भरता रखी थी, जबकि दूसरी ओर, दावेदार कंपनी ने भारत संघ बनाम डी. पी. सिंह *(3)* पर भरोसा किया था।अजीत मेहता के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले और बृज भूषण के मामले पर भरोसा किया था।हालाँकि, नंद्याल को-ऑप के मामले में भारत का माननीय सर्वोच्च न्यायालय।1993(2) एस. सी. सी. 654 ने बंबई उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया और अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों को लागू करने के संबंध में इसे अलग किया। इसके अलावा, बॉम्बे उच्च न्यायालय, किसी भी मामले में, भारत संघ के लिए ज्यादा मददगार नहीं है क्योंकि यह प्रारंभिक नियुक्ति का मामला था जैसा कि निर्णय के पैराग्राफ संख्या 19 में न्यायालय द्वारा बताए गए तथ्यों से स्पष्ट है।डी. पी. सिंह के मामले में पटना उच्च न्यायालय के फैसले का वर्तमान मामले के तथ्यों पर असर पड़ा है।हम पक्षकारों द्वारा भरोसा किए गए उच्च न्यायालयों के निर्णयों पर आगे या बहुत विस्तार से चर्चा करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं, मुख्य रूप से इस कारण से कि मुद्दे में विवाद का निपटारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों द्वारा किया जाता है, जिसका हम वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अधिक विशेष रूप से पालन करने के लिए बाध्य हैं।

(20) इसके अलावा, भारत संघ बनाम मेसर्स हरबंस सिंह तुली एंड संस बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में निर्भरता रखी है।

(1) ए. आई. आर. 1990 बॉम्बे 45.
(2) ए. आई. आर. 1972 पी. एंड एच. 266.
(3) ए. आई. आर. 1961 पटना 228.

भारत संघ (4), जहाँ न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः—

> "धारा 8 एक मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए एक सरल तंत्र प्रदान करती है, शुरू में या रिक्तता की आपूर्ति के लिए यदि उक्त रिक्ति मध्यस्थता की अवधि के दौरान होती है।उप-धारा((क) मध्यस्थ या मध्यस्थों की प्रारंभिक नियुक्ति के मामले में लागू होगा।इसका निहितार्थ मध्यस्थता समझौते में है, मध्यस्थ या मध्यस्थों का नाम नहीं लिया जाना चाहिए।अतः जहाँ उनका नाम दिया गया है, वहाँ इस धारा का कोई उपयोग नहीं होगा। इसी तरह, मध्यस्थ या मध्यस्थों को सभी पक्षों द्वारा सहमति के साथ नियुक्त किया जाना आवश्यक है।इसके विपरीत, यदि नियुक्ति का कोई अन्य तरीका है, उदाहरण के लिए, धारा 4, जहां समझौते के पक्षकार इस बात पर सहमत हैं कि मध्यस्थ की नियुक्ति समझौते में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा या तो पद पर रहने के नाम से की जानी है, तो निश्चित रूप से यह धारा लागू नहीं होगी।तत्काल मामले में सी. पी. एन. टी. आर. टी. के खंड में प्रावधान किया गया है कि मध्यस्थ की नियुक्ति मुख्य अभियंता द्वारा की जानी है।यदि वह मध्यस्थ इस्तीफा दे देता है या अपना पद खाली कर देता है या किसी न किसी कारण से असमर्थ या अनिच्छुक है, तो वह दूसरा मध्यस्थ नियुक्त कर सकता है। उक्त खंड के तहत क्रमिक मध्यस्थों की नियुक्ति की गई थी, यहां तक कि रिक्तियों की आपूर्ति वास्तव में मुख्य अभियंता द्वारा की गई थी।इसलिए, इन परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि धारा 8 (1) (बी) के तहत शर्तों को पूरा किया गया था, परिणामस्वरूप न्यायालय द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति अवैध होगी और तर्क की प्रक्रिया के माध्यम से मामले को उसके उचित परिप्रेक्ष्य में विचार किए बिना उसके द्वारा पारित पुरस्कार को रद्द कर दिया जाएगा।"

(21) उस मामले के तथ्यों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ यह हैं कि धारा 8 का खंड 1 (ए) मध्यस्थ की प्रारंभिक नियुक्ति पर लागू होगा और उनके अधिपतियों ने पाया कि अधिनियम की धारा 8 (एल) (बी) के आवेदन के लिए पूर्ववर्ती शर्तें उस मामले में संतुष्ट नहीं थीं।पैराग्राफ नं. 23 निर्णय कि प्रतिवादी, नोटिस के 15 दिनों की समाप्ति पर एक मध्यस्थ नियुक्त करने का अधिकार खो देगा, लेकिन उस मामले में ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी।ये वर्तमान मामले पर सीधे लागू होने वाले सर्वोच्च न्यायालय के अन्य महत्वपूर्ण फैसलों के अलावा कुछ विशिष्ट विशेषताएं हैं, जिन पर हम जल्द ही चर्चा करेंगे।

(22) भारत संघ के विद्वान वकील द्वारा भरोसा किया गया दूसरा मामला श्री भूपिंदर सिंह बिंद्रा बनाम भारत संघ और अन्य का है।

न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों पर जोर देते हुएः—

> "यह पक्षकार की अपनी इच्छा या खुशी से उसकी सहमति से नियुक्त मध्यस्थ के अधिकार को रद्द करने की शक्ति में नहीं है।अदालत के लिए मध्यस्थ नियुक्त करने की कोई सामान्य शक्ति नहीं है जब तक कि मामला अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के भीतर नहीं आता है और न ही अदालत एक नियुक्ति करती है जहां मध्यस्थता समझौता एक विधि प्रदान करता है जिसके द्वारा नियुक्ति की जानी है।"

(23) इस मामले में न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जहां समझौते की शर्तों के तहत एक नामित मध्यस्थ प्रदान किया गया था और मध्यस्थ के अधिकार को निरस्त करने का कोई उचित और पर्याप्त कारण नहीं है, वहां न्यायालय ऐसे मध्यस्थ की नियुक्ति में हस्तक्षेप करने का हकदार नहीं है।इस निर्णय में अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि पक्षकारों ने इस तरह के समझौते की शर्तों के लिए सहमति दी और उन्होंने मध्यस्थ के समक्ष भाग लिया और मध्यस्थ की ओर से कोई कदाचार नहीं होने के कारण, न्यायालय मध्यस्थ की नियुक्ति में उचित नहीं हो सकता है।हम इन सिद्धांतों को

वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करने और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए अन्य निर्णयों पर चर्चा करने के बाद भी चर्चा करेंगे।

(24) मध्यस्थता अधिनियम की धारा 5,8,11,12,20 और 31 जैसे प्रावधानों को लंबे समय से विभिन्न व्याख्याओं के अधीन किया गया है, लेकिन अधिनियम की धारा 31 के अर्थ और दायरे के भीतर सक्षम न्यायालय की अधिकार क्षेत्र के पूर्ण बहिष्कार को अब तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है।एक बार जब पूर्व-नोटिस किए गए किसी भी विशेष प्रावधान के आवेदन के लिए पूर्ववर्ती सामग्री और शर्तें संतुष्ट हो जाती हैं, तो न्यायालय के पास मध्यस्थ की नियुक्ति सहित उचित आदेश पारित करने का अधिकार क्षेत्र होता है।न्यायालय के लिए न तो यह सलाह दी जाएगी और न ही उचित होगा कि वह इस तरह के कानून के प्रस्ताव के लिए एक सीधा सूत्र प्रदान करे क्योंकि प्रत्येक मामले का निर्णय अपने गुण-दोष के आधार पर किया जाता है और निर्धारित किया जाता है।वर्तमान मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ समय बीतने के परिणामस्वरूप एक तरह से जटिल हैं, लेकिन जैसा कि पूर्व-उल्लिखित परिस्थितियों से स्पष्ट है कि न्यायालयों ने एक विशेष प्रावधान के तहत सामग्री की पूर्ति पर एक मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया था और ऐसे आदेश पक्षों द्वारा स्वीकार किए गए थे और वर्ष 1989 और 1993 में अंतिम रूप से प्राप्त किए गए थे।

(25) अब हम अधिनियम की धारा 8 के तहत एक आवेदन की रखरखाव के संबंध में कानूनी सिद्धांतों के प्रतिपादन और अधिनियम के तहत याचिकाओं पर विचार करने के लिए अन्यथा सक्षम न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली अधिकारिता के दायरे के संबंध में इसके अनुप्रयोग पर चर्चा करने के लिए आगे बढ़ेंगे।

(26) मेसर्स प्रभात जनरल एजेंसीज आदि बनाम भारत संघ और अन्य *(6)* के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय एक नामित मध्यस्थ से संबंधित मध्यस्थता खंड से संबंधित था।हिमाचल प्रदेश के न्यायिक आयुक्त नामित मध्यस्थ थे, जिनके निर्णय को अंतिम और पक्षों के लिए बाध्यकारी माना गया था।न्यायिक आयुक्त ने मध्यस्थ के रूप में कार्य करने से इनकार कर दिया और उस संदर्भ में न्यायालय ने अधिनियम की धारा 8 (एल) (बी) और 20 के दायरे पर इस मूल सिद्धांत पर विचार किया कि क्या पक्ष रिक्तियों की आपूर्ति करना चाहते हैं या नहीं।न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः—

> "धारा 20 केवल एक मशीनरी प्रावधान है।पक्षकारों के मूल अधिकार धारा 8 (1) (बी) में पाए जाते हैं।धारा 8 (1) (बी) के लागू होने से पहले यह दिखाया जाना चाहिए कि (1) विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजने के लिए पक्षों के बीच एक समझौता है; (2) उन्होंने अपने विवाद को हल करने के लिए एक मध्यस्थ या मध्यस्थ या अंपायर नियुक्त किया होगा; (3) उन मध्यस्थों या अंपायरों में से किसी ने या अधिक ने लापरवाही की होगी या कार्य करने से इनकार कर दिया होगा या कार्य करने में असमर्थ है या उनकी मृत्यु हो गई होगी; (4) मध्यस्थता समझौते से यह नहीं पता चलना चाहिए कि यह उद्देश्य था कि रिक्ति को नहीं भरा जाना चाहिए; और (5) पक्ष या मध्यस्थों ने मामले में रिक्ति की आपूर्ति नहीं की होगी।
>
> हमारे समक्ष मामलों में यह स्वीकार किया जाता है कि ये विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का एक समझौता है।यह भी स्वीकार किया जाता है कि पक्षों ने समझौते के संबंध में उनके बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को हल करने के लिए हिमाचल प्रदेश के न्यायिक आयुक्त को मध्यस्थ के रूप में नामित किया था।न्यायिक आयुक्त ने मध्यस्थ के रूप में कार्य करने से इनकार कर दिया था।पार्टियों ने उस रिक्ति की आपूर्ति नहीं की है।इसलिए, एकमात्र सवाल यह है कि क्या समग्र रूप से पढ़ा गया समझौता या तो स्पष्ट रूप से या निहित रूप से दर्शाता है कि पक्षों का इरादा था कि रिक्ति की आपूर्ति नहीं की जानी चाहिए।यह ध्यान दिया जा सकता है कि प्रावधान की भाषा यह नहीं है कि पार्टियों ने रिक्ति की आपूर्ति करने का इरादा किया था, बल्कि दूसरी ओर यह है कि 'पार्टियों का रिक्ति की आपूर्ति करने का इरादा नहीं था'।दूसरे शब्दों में, यदि वह समझौता रिक्ति की आपूर्ति के संबंध में मौन है, तो कानून यह मानता है कि पक्ष रिक्ति की आपूर्ति करने का इरादा रखते हैं।मामले को धारा 8 (1) (बी) से बाहर निकालने के लिए आवश्यक है कि पार्टियों का इरादा रिक्ति की आपूर्ति करने का नहीं है, बल्कि उनका इरादा रिक्ति की आपूर्ति करने का नहीं है।अब हमें यह देखना होगा कि क्या हमारे सामने किए गए समझौते इस तरह के इरादे का संकेत देते हैं।"

उच्चतम न्यायालय ने वास्तव में अपीलों को स्वीकार करते हुए उस मामले में विद्वत विचारण न्यायालय को एक मध्यस्थ नियुक्त करने का निर्देश दिया।

(27) चंदर भान हर्भजन लाल बनाम पंजाब राज्य *(7)* के मामले में फिर से न्यायालय एक मध्यस्थता खंड से संबंधित था जिसमें सरकार को विवादों के निपटारे के लिए समिति को नामित करने की आवश्यकता थी जिसका निर्णय अंतिम होना था।सरकार ने एक समिति नियुक्त की लेकिन इसके समापन से पहले समिति को समाप्त कर दिया गया।दूसरी समिति ने संदर्भ में प्रवेश किया और पंचॉट पारित किया।सिविल कोर्ट ने इस पंचाट को रद्द कर दिया था।सरकार ने अपीलार्थी को एक नए मध्यस्थ की नियुक्ति पर सहमति देने के लिए नोटिस दिया, जिसका जवाब नहीं दिया गया और अदालत ने नई समिति नियुक्त की।न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः—

> "हम समान रूप से स्पष्ट हैं कि धारा 8 के तहत न्यायालय कार्य करने और एक समिति नियुक्त करने का हकदार है।जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि जब दूसरी निपटान समिति ने काम करना बंद कर दिया तो समिति "कार्य करने में असमर्थ" हो गई और इसलिए यह अदालत की क्षमता के भीतर था कि वह एक नई समिति नियुक्त करने के लिए आगे बढ़े।समान रूप से यह तर्क भी असमर्थनीय है कि धारा 8 उन मामलों में लागू नहीं होती है जहां शर्त एक पक्ष द्वारा निपटान समिति की नियुक्ति को निर्धारित करती है।यह निवेदन धारा के शब्दों पर भरोसा करते हुए किया गया था कि कोई भी पक्ष अन्य पक्षों या मध्यस्थों को, जैसा भी मामला हो, नियुक्ति या नियुक्तियों में सहमति देने या रिक्ति की आपूर्ति करने के लिए एक लिखित सूचना के साथ सेवा दे सकता है।इस धारा के इस भाग में निस्संदेह दो पक्षों पर विचार किया गया है, लेकिन इस धारा को लागू नहीं होने के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है, जहां समझौते में एक पक्ष द्वारा समिति के नामांकन के लिए प्रावधान किया गया है, जिसमें कहा गया है कि पार्टी अन्य पक्षों की सेवा कर सकती है।"अन्य पक्षों की सेवा कर सकते हैं "जिसमें उन मामलों में अन्य पक्षों की सेवा नहीं करना शामिल होगा जिनमें दूसरे पक्ष की सेवा पर विचार नहीं किया गया है।"

(28) यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मेसर्स आरबी सीएच के मामले में। रघुनाथ सिंह एंड कंपनी (8), माननीय उच्चतम न्यायालय ने हालांकि मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए नामित पद के उन्मूलन की स्थिति में भी मध्यस्थ के नाम वाले मध्यस्थता खंड पर फिर से विचार करते हुए, समझौते में पक्षों के इरादे के सिद्धांत पर प्रकाश डाला कि रिक्तता की आपूर्ति करने का इरादा नहीं था क्योंकि यह बुनियादी विचारों में से एक था।

(7) ए. आई. आर. 1971 एस. सी. 1210.
(8) (1979) 4 एस. सी. सी 21

अधिनियम की धारा 8 (1) (बी) के तहत आवेदन के लिए विचार किया गया, जो निम्नानुसार हैः—

"हालांकि, मुख्य आयुक्त उपलब्ध थे लेकिन उन्होंने कार्रवाई करने से इनकार कर दिया।इसके कारण प्रतिवादी कंपनी ने एक अन्य मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अधिनियम की धारा 8 के तहत अदालत में आवेदन किया।अपीलार्थी की ओर से यह तर्क दिया गया है कि जब एक नामित मध्यस्थ था, भले ही उसे कार्यालय द्वारा नामित किया गया था, तो अधिनियम की धारा 8 (1) (बी) के तहत उसके स्थान पर रिक्ति की आपूर्ति करने के लिए अदालत के लिए यह खुला नहीं था। हम इस तर्क में कोई सार नहीं पाते हैं।अदालत के पास धारा 8 (1) (बी) के तहत रिक्ति की आपूर्ति करने की कोई शक्ति नहीं थी, केवल तभी जब मध्यस्थता समझौते से पता चलता है कि पक्षकारों का रिक्ति की आपूर्ति करने का इरादा नहीं था।यदि ऐसा कोई इरादा मध्यस्थता खंड से नहीं निकाला जा सकता है, तो अदालत रिक्ति की आपूर्ति कर सकती है।मेसर्स प्रभात जनरल एजेंसीज बनाम भारत संघ में इस न्यायालय का एक सीधा निर्णय है।

हमारी राय में अधिनियम की धारा 8 (1) (बी) के प्रावधानों पर विचार करते समय, उस निर्णय से अपीलार्थी को कोई मदद नहीं मिलेगी।पूर्ण पीठ का निर्णय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की अनुसूची II में पैराग्राफ 5 में निहित कानून के संबंधित प्रावधानों के संदर्भ में दिया गया था, जिसमें अधिनियम की धारा 8 (1) (बी) में आने वाले महत्वपूर्ण शब्द नहीं थे।धारा 8 (1) (बी) के शब्द ये हैं:"और मध्यस्थता समझौता यह नहीं दर्शाता है कि यह इरादा था कि रिक्ति की आपूर्ति नहीं की जानी चाहिए।"

(29) ऐसा प्रतीत होता है कि हाल के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने निचली अदालतों द्वारा प्रयोग की जाने वाली अधिकारिता के दायरे और अधिनियम की धारा 8 (1) (बी) के प्रावधानों के तहत एक आवेदन की रखरखाव क्षमता का खर्च किया है। पश्चिम बंगाल राज्य बनाम राष्ट्रीय बिल्डर (9) के मामले में, जहां न्यायालय मध्यस्थता खंड से संबंधित था, जहां पक्षों के बीच विवाद को मुख्य अभियंता या मुख्य अभियंता द्वारा नियुक्त मध्यस्थ को भेजा जाना था, यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया थाः—

"अतः, यह इस प्रकार है कि ऐसे मामले में जहां मध्यस्थता खंड एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति का प्रावधान करता है और उसने कार्रवाई करने से इनकार कर दिया था, तब समझौते का खंड समाप्त हो जाता है।और यह अदालत पर है कि वह धारा 8 (1) (बी) के तहत हस्तक्षेप करे और एक अन्य मध्यस्थ नियुक्त करे, 'यदि मध्यस्थता समझौते से यह नहीं पता चलता है कि यह इरादा था कि रिक्ति की आपूर्ति नहीं की जानी चाहिए'।यानी समझौते पर औरमध्यस्थता की रोक नहीं लगनी चाहिए।

(9) 1994(1) एस. सी. सी 235

।यदि समझौते में यह प्रावधान किया गया है कि यदि समझौते के अनुसार नियुक्त मध्यस्थ कार्रवाई करने से इनकार करता है तो विवाद को किसी अन्य मध्यस्थ द्वारा हल किया जाएगा, तो मामला समाप्त हो जाएगा।लेकिन अगर समझौता यह नहीं दिखाता है तो अगला मध्यस्थ केवल अदालत द्वारा नियुक्त किया जा सकता है।उप-धारा में प्रयुक्त अभिव्यक्ति स्पष्ट संकेत है कि न्यायालय को अपनी शक्ति का प्रयोग करने से केवल तभी रोका गया है जब पक्षकारों का इरादा हो कि रिक्ति को नहीं भरा जाना चाहिए।दूसरे शब्दों में, न्यायालय किसी अन्य मध्यस्थ को नियुक्त करने के लिए अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करेगा, सिवाय इसके कि जहां उसे ऐसा करने से विशेष रूप से प्रतिबंधित किया गया है।खंड में प्रयुक्त 'शो' शब्द महत्वपूर्ण प्रतीत होता है।वास्तव में यह अभिव्यक्ति के निर्माण की कुंजी प्रस्तुत करता है।केवल उपेक्षा या अकेले कार्य

करने से इनकार करना अदालत को हस्तक्षेप करने का अधिकार देने के लिए पर्याप्त नहीं है।समझौते को आगे यह नहीं दिखाना चाहिए कि पक्षों का इरादा था कि रिक्ति की आपूर्ति नहीं की जाएगी।इसके विपरीत स्पष्ट शब्दों या स्पष्ट भाषा के अभाव में इसे सकारात्मक रूप से रखने के लिए अदालत एक और मध्यस्थ नियुक्त कर सकती है। इस शब्द का वास्तविक प्रभाव यह है कि यह शक्ति का प्रयोग करने के लिए न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करता है, यदि समझौता विशेष रूप से इसे ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं करता है।इसे सरल शब्दों में कहें तो मध्यस्थ को हस्तक्षेप करने और नियुक्त करने की अदालत की शक्ति तब लागू होती है जब मध्यस्थ कार्रवाई करने से इनकार कर देता है और समझौते से यह नहीं पता चलता है कि पक्षों का इरादा नहीं था कि रिक्ति की आपूर्ति नहीं की जाएगी।प्रभात जनरल एजेंसी बनाम भारत संघ मामले में इस न्यायालय ने यह निर्णय दिया थाः(1971) 1 पी. 82 पर एस. सी. सी. 79, पैरा 4)

> " कि प्रावधान की भाषा यह नहीं है कि पक्षों ने 'रिक्ति' की आपूर्ति करने का इरादा किया था, बल्कि दूसरी ओर यह है कि 'पार्टी ने रिक्ति की आपूर्ति करने का इरादा नहीं किया था'।दूसरे शब्दों में यदि समझौता रिक्ति की आपूर्ति के संबंध में मौन है तो कानून यह मानता है कि पक्ष रिक्ति की आपूर्ति करने का इरादा नहीं है।धारा 8(1)(बी) के परिप्रेक्ष्य से मामले को बाहर निकालने के लिए जरूरी नहीं है कि पार्टियों का इरादा रिक्ति को भरने का हो, बल्कि यह है कि उनका इरादा रिक्ति को नहीं भरने का हो।

"यह मध्यस्थता के इस आधार के विपरीत होगा कि किसी को भी उसकी स्वतंत्र इच्छा के खिलाफ कार्य करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।यह समझौते के विपरीत भी होगा और यदि उनका किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करने का कोई समझौता नहीं है, तो एकमात्र उपाय यह है कि वे अपनी वैधानिक शक्ति का प्रयोग करने और किसी अन्य मध्यस्थ को नियुक्त करने के लिए अदालत से संपर्क करें।वही परिणाम आता है जहाँ मध्यस्थता खंड एकमात्र मध्यस्थ को या तो स्वयं मध्यस्थता करने या किसी और को नामित करने का अधिकार देता है।यह आग्रह किया गया था कि सिद्धांत

जहां एकमात्र मध्यस्थ को किसी अन्य व्यक्ति को नामित करने की शक्ति दी गई है, वहां समाप्त होने वाला समझौता खंड लागू नहीं हो सकता है।विद्वान वकील के अनुसार एक बार जब नामित व्यक्ति ने कार्य करने से इनकार कर दिया तो मुख्य अभियंता को फिर से अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नामित करने का अधिकार दिया गया।हमारी राय में प्रस्तुत करना कानून में अच्छी तरह से स्थापित नहीं है।एकमात्र मध्यस्थ द्वारा नामित व्यक्ति को उसके स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाता है।उनका कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं है।उनके द्वारा प्रयोग की गई शक्ति और अधिकार उसी अधिकार के समान है जिसने उन्हें नामित किया था।इसलिए, एक बार जब नामित व्यक्ति कार्य करने से इनकार कर देता है तो यह माना जाएगा कि मध्यस्थता खंड में उल्लिखित मध्यस्थ ने कार्य करने से इनकार कर दिया है और इसलिए, खंड उसी तरह से कार्य करना बंद कर देगा जैसे मुख्य अभियंता ने स्वयं कार्य करने से इनकार किया है।अगले मध्यस्थ की नियुक्ति केवल अधिनियम की धारा 8 (1) (बी) के अनुसार हो सकती है।

(30) नंद्याल को-ऑपरेटिव स्पिनिंग मिल्स बनाम के. वी. मोहन राव *(10)* के मामले के बाद जी. रामचंद्र रेड्डी एंड कंपनी बनाम अभियंता, मद्रास क्षेत्र, सैन्य अभियांत्रिकी सेवा *(11)*।उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक मध्यस्थ की नियुक्ति करने की न्यायालय की शक्ति काफी व्यापक है और एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को इस तरह के इरादे की सूचना दिए जाने के बाद एक मध्यस्थ की नियुक्ति की जा सकती है।

(31) मोहिंदर कुमार जैन बनाम ब्यास निर्माण बोर्ड और एक अन्य (12) नामक एक बहुत ही हाल के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय उस अनुबंध में मध्यस्थता समझौते के खंड 25 ए पर विचार कर रहा था।उस खंड के अनुसार विवाद को मुख्य अभियंता/विद्युत ब्यास परियोजना द्वारा नियुक्त मध्यस्थ को भेजा जाना था।दूसरे शब्दों में, परियोजना के मुख्य अभियंता नामित प्राधिकारी थे जबकि परियोजना के एक्स. ई. एन. इलेक्टिकल और ठेकेदार मध्यस्थता के पक्षकार थे।न्यायालय द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति को बरकरार रखते हुए न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:—

> "अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने नंद्याल को-ऑप में इस न्यायालय के फैसले की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया।स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड बनामके. वी. मोहन राव, जिन्होंने एक समान स्थिति पर व्यापक रूप से विचार किया है और यह विचार रखा है कि जहां एक अनुबंध एक पक्ष को एक मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए अधिकृत करता है, लेकिन उस पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष द्वारा दिए गए नोटिस में निर्धारित समय के भीतर किसी भी मध्यस्थ की नियुक्ति नहीं की जाती है, अदालत को अधिनियम की धारा 8 के संदर्भ में अधिकार क्षेत्र मिलेगा।
>
> (10) 1993 (2) एस. सी. सी 654
> (11) 1994 (5) एस. सी. सी. 142.
> (12) 1999 (2) मध्यस्थता विधि रिपोर्टर 566 (एससी)।
>
> वर्तमान मामले के तथ्यों पर उपरोक्त सिद्धांत को लागू करते हुए, हम उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश को दरकिनार करते हैं और निचली अदालत के आदेश को बहाल करते हैं।अब विचारण न्यायालय द्वारा नियुक्त मध्यस्थ मामले को यथासंभव शीघ्रता से आगे बढ़ाएगा।"

(32) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए कानून के पूर्व-सूचित सिद्धांतों की विश्लेषणात्मक जांच से पता चलेगा कि दावेदार-भारत संघ द्वारा दिए गए निर्णयों पर भी भरोसा किया जाता है।हरबंस सिंह तुली और उनके बेटे *(ऊपर)* और भूपिंदर सिंह बिंद्रा *(ऊपर)* न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को पूरी तरह से हटाने के प्रस्ताव का समर्थन नहीं करते हैं यदि मामला मध्यस्थता अधिनियम के किसी भी प्रासंगिक प्रावधान के तहत आता है। हरबंस सिंह तुली के मामले (उपरोक्त) में न्यायालय ने वैधानिक अवधि की समाप्ति पर मध्यस्थ नियुक्त करने के अधिकार को जब्त करने

के सिद्धांतों को बरकरार रखा।इसके अलावा, उनके अधिपतियों ने इस सवाल को खुला छोड़ दिया कि क्या ऐसी नियुक्ति के लिए धारा 20 के तहत आवेदन दायर किया जा सकता है।उस मामले में ऐसे सिद्धांतों के लिए आवेदन मध्यस्थ की प्रारंभिक नियुक्ति से संबंधित है।जबकि, भूपिंदर सिंह बिंद्रा (ऊपर) के मामले में धारा 8 के तहत मध्यस्थ नियुक्त करने की न्यायालय की शक्ति को बरकरार रखा गया था, निश्चित रूप से, इस परंतुक के अधीन कि मामला अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के भीतर आता है।

(33) यह हमारे सामने शायद ही विवाद में है कि दावेदार कंपनी द्वारा विधिवत नोटिस दिया गया था जिसमें नामित प्राधिकारी के साथ-साथ भारत संघ को रिक्ति की आपूर्ति करने और साथ ही एक मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए कहा गया था।भारत संघ तीसरी बार भी इस तरह के अधिकार का प्रयोग करने में विफल रहने के बाद, दावेदार कंपनी ने मध्यस्थ ब्रिगेडियर परिहार को हटाने का अनुरोध करते हुए अदालत के समक्ष तीसरा आवेदन दायर किया क्योंकि परिहार ने अधिनियम की धारा 8 के दायरे और दायरे में स्वतंत्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए कार्य करने की उपेक्षा की थी। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि ब्रिगेडियर।परिहार कार्रवाई करने में विफल रहे थे, और किसी भी मामले में, इस बीच उनके इस्तीफे के कारण, अदालत ने एक स्वतंत्र मध्यस्थ नियुक्त किया था।

(34) विधानमंडल ने अपने विवेक में अधिनियम की धारा 8 (1) (बी) में "यदि कोई नियुक्त मध्यस्थ" अभिव्यक्ति का उपयोग किया था। इस अभिव्यक्ति को एक सीमित अर्थ या सीमित दायरा देने के लिए क़ानूनों की व्याख्या के किसी भी स्वीकृत सिद्धांत पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है। चाहे मध्यस्थ को पक्षों द्वारा सहमति से या किसी अन्य तरीके से नियुक्त किया गया था, जैसा कि धारा 8 (1) (बी) में संदर्भित है, इस तरह के किसी भी भेद को स्वीकार नहीं करता है।अधिनियम के दायरे और दायरे के भीतर विभिन्न तरीकों से नियुक्त मध्यस्थों को उस सीमित उद्देश्य के लिए बराबर माना जाना चाहिए।अधिनियम की धारा 8 (1) (बी) के तहत आवेदन के लिए सर्वोपरि विचार यह है कि पक्षों के बीच एक मध्यस्थता समझौता है और यह नहीं दर्शाता है कि इसका उद्देश्य यह था कि रिक्तियों की आपूर्ति नहीं की जानी चाहिए।यदि पक्ष रिक्तता की आपूर्ति करने में विफल रहते हैं, तो उस स्थिति में अधिनियम की धारा 8 (1) (बी) के तहत मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए सक्षम न्यायालय की अधिकारिता को पूरी तरह से हटाने का कोई सिद्धांत या कानून नहीं है। यह सिद्धांत, निश्चित रूप से, इस शर्त के अधीन है कि आवेदन को अधिनियम की धारा 8 (1) (बी) की पूर्व शर्तों को पूरा करना होगा। यह प्रभात जनरल एजेंसियों; नंद्याल शिपिंग मिल्स लिमिटेड; नेशनल बिल्डर्स; मोहिंदर कुमार जैन और रघुनाथ सिंह में सर्वोच न्यायालय द्वारा स्थापित सिंधांतो का संचय प्रभाव है।

(35) प्रभात जनरल एजेंसी (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिनियम की धारा 8 (1) (बी) को लागू करने की पूर्व शर्त वर्तमान मामले में पूरी तरह से संतुष्ट है। मध्यस्थ की नियुक्ति न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना और समझौते के खंड 70 के तहत निर्धारित तंत्र के तहत पक्षों की सहमति पर तीन अलग-अलग अवसरों पर नामित प्राधिकरण द्वारा की गई थी। इसके बाद, न्यायालय द्वारा मध्यस्थों की नियुक्ति की गई, जिन्हें पक्षकारों ने स्वेच्छा से स्वीकार किया या ऐसे आदेशों को कानून में या अन्यथा अंतिमता प्राप्त हुई।विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजने के लिए पक्षों के बीच एक समझौता था।एक नियुक्त मध्यस्थ था।मध्यस्थों ने उपेक्षा की थी या इनकार कर दिया था या अपने इस्तीफे के कारण या अन्यथा अक्षम हो गए थे।समझौते से यह नहीं पता चलता है कि पार्टियों का रिक्ति की आपूर्ति करने का इरादा नहीं था और रिक्ति वास्तव में सूचना के बाद प्रदान नहीं की गई थी।वर्तमान मामले में शर्तों को पूरा करने के कारण हम न्यायालय द्वारा एक स्वतंत्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवेदन की स्थिरता के संबंध में भारत संघ की आपत्ति के आधार को समझने में असमर्थ हैं।वर्तमान मामला प्रारंभिक नियुक्ति का नहीं है, बल्कि स्वयं न्यायालय द्वारा नियुक्त किए जाने वाले क्रमिक मध्यस्थों का है।नोटिस के प्रावधानों का पालन न करने से निश्चित रूप से नामित प्राधिकारी द्वारा अपने अधिकार का त्याग करने और सक्षम न्यायालय द्वारा अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए प्रतिबंध, यदि कोई हो, को हटाने का प्रभाव पड़ेगा।यह भी

स्पष्ट है कि पहले नियुक्त किए गए विभिन्न मध्यस्थों ने मध्यस्थ द्वारा इस्तीफे के रूप में कार्य करने से भी इनकार कर दिया था, जो मामले को आगे नहीं बढ़ाने के उसके इरादे की अभिव्यक्ति होगी।जहाँ न्यायालय इन घटकों से संतुष्ट है, वहाँ न्यायालय के लिए ऐसी रिक्ति की आपूर्ति करने के लिए कोई बाधा नहीं होगी।राष्ट्रीय बिल्डरों (उपर्युक्त) के मामले में, जहां एक नामित मध्यस्थ के साथ-साथ नामित प्राधिकारी द्वारा नामित मध्यस्थ था, शीर्ष अदालत ने माना था कि नियुक्त मध्यस्थ के इनकार करने या कार्य करने से इनकार करने की स्थिति में, मध्यस्थ नियुक्त करने की अदालत की शक्ति को बरकरार रखा गया था।

(36) एक अन्य विचार जो इस न्यायालय के साथ विचार करने योग्य है, वह है वर्तमान पुनरीक्षण में चुनौती दिए गए आदेशों के संबंध में पूर्व न्याय या आण्वायिक पूर्व न्याय के सिद्धांतों का अनुप्रयोग।यह दलील है,

हालाँकि, छूट की याचिका के विरोध में नहीं, जैसा कि ऊपर चर्चा की गया है।भारत संघ ने स्वयं अंतिम रूप प्राप्त करने के लिए मध्यस्थों की नियुक्ति के संबंध में 30 मई, 1989 और 16 फरवरी, 1991 के विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित दो आदेशों को स्वीकार किया था और अनुमति दी थी।दूसरे शब्दों में, सक्षम अधिकार क्षेत्र की अदालत ने अदालत के समक्ष उठाए गए विवादों पर निर्णय लेने के बाद एक आदेश पारित किया था।विवादित आदेश में भी महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि क्या न्यायालय पिछले मध्यस्थ को हटाकर मामले की परिस्थितियों में मध्यस्थ नियुक्त कर सकता है या नहीं?इस प्रश्न का उत्तर विद्वत विचारण न्यायालय ने अपने पिछले आदेश में स्पष्ट रूप से दिया था।अधिनियम के तहत प्रत्येक याचिका अपने आप में एक वाद या याचिका के रूप में दर्ज की जाती है, लेकिन भले ही हम इसे मुख्य मध्यस्थता कार्यवाही की प्रगति के लिए अंतर्वर्ती आदेश मानते हैं, फिर भी सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 141 की सहायता, वाद की प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत तय किए जाने वाले आवेदनों पर भी लागू होती है।दूसरे शब्दों में, पूर्व न्यायिकता का सिद्धांत तब तक अंतरिम आदेशों पर भी लागू होगा जब तक कि वे पूर्व न्यायिकता के सिद्धांतों के गैर-अपवादों के तहत नहीं आते।इस संबंध में, अर्जुन सिंह बनाम मोहिंद्र कुमार और अन्य (13) शीर्षक वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय और जयपाल बनाम श्रीमती के मामले में इस न्यायालय का संदर्भ दिया जा सकता है। भागमाली और अन्य, *1998* का सिविल पुनरीक्षण संख्या *4717,12* अगस्त, *1999* को तय किया गया।

(37) वर्तमान मामले में मध्यस्थता समझौता अर्थात अनुबंध का खंड 70 स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित करता है कि पक्षकार रिक्तियों की आपूर्ति करेंगे।इस प्रकार, यह ऐसा मामला नहीं है जहां पक्षों के बीच मध्यस्थता समझौते का उद्देश्य रिक्ति की आपूर्ति नहीं करना है और आगे मध्यस्थता कार्यवाही को जारी रखना प्रतिबंधित है।दूसरे शब्दों में, मध्यस्थता की कार्यवाही को समाप्त नहीं किया जाना था यदि रिक्तता किसी नियुक्त मध्यस्थ द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त तरीके से हुई थी।धारा 20 केवल एक तंत्र है और पक्षों के मूल अधिकार अधिनियम की धारा 8 (1) (बी) द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं।

(38) हमारे समक्ष यह तर्क दिया गया था कि मुख्य अभियंत समझौते का तीसरा पक्ष नहीं था, बल्कि वास्तव में भारत संघ का अभिन्न अंग था और अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों को किसी भी मामले में आकर्षित नहीं किया जाएगा।हमने देखा है कि इंजीनियर-इन-चीफ उन मुख्य इंजीनियरों का प्रमुख होता है जो इस तरह के समझौते में प्रवेश करते हैं।यद्यपि वह एक नियुक्ति प्राधिकारी है और वह कार्य करने में विफल रहा है, भारत संघ को उस आधार पर कोई अनुचित लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।हम इस विवाद को वहीं छोड़ देंगे।

(39) मध्यस्थता खंड और कार्यवाहियां मुख्य रूप से पक्षों की सहमति पर आधारित होती हैं। दूसरे शब्दों में आपसी सहमति का सार है

मध्यस्थता कानून।भारत संघ ने न्यायालय द्वारा की गई दो नियुक्तियों को स्वीकार कर लिया और बिना किसी विरोध के उक्त मध्यस्थों के समक्ष भाग लिया।प्रारंभिक नियुक्तियों में सहमति जताने के बाद हम यह भी नहीं समझते हैं कि भारत संघ की ओर से न्यायालय के समक्ष इस तरह की नियुक्ति और आवेदन की रखरखाव पर आपत्ति जताना उचित होगा।

(40) भले ही, तर्कों के लिए,अगर हम मानते हैं कि धारा 8 के तहत आवेदन दावेदार कंपनी द्वारा दायर मध्यस्थ के समक्ष बनाए रखने योग्य नहीं था, भारत संघ ने स्वयं पहले आवेदन के जवाब में धारा 8 के तहत आवेदन दायर किया था और अदालत ने पक्षों द्वारा सुझाए गए पैनल में से एक मध्यस्थ नियुक्त किया था।दलों ने नियुक्ति को स्वीकार किया और बिना किसी विरोध या विरोध के इस तरह के आदेशों को आगे बढ़ाने के लिए उन कार्यवाही में भाग लिया।उनके शब्दों में, पक्षकारों ने न्यायालय के समक्ष मध्यस्थों अर्थात् ब्रिगेडियर परिहार और श्री वाधवा की नियुक्ति में सहमति व्यक्त की ।दलों के पास अपने विचार व्यक्त करने और उस स्तर पर उनके लिए उपलब्ध उचित उपायों का सहारा लेने का हर अवसर था।पहली नियुक्ति में किसी भी पक्ष द्वारा आदेश पर हमला करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया था और दोनों ने इसे स्वीकार कर लिया और इस प्रकार, रखरखाव के कारण उक्त नियुक्ति को चुनौती देने के लिए विबंध कर दिया जाएगा।दूसरी नियुक्ति में, भारत संघ द्वारा आदेश पर हमला किया गया और सर्वोच्च न्यायालय तक हार गया।इस प्रकार दूसरी नियुक्ति भी कानून के अनुसार अंतिम हो गई।न्यायालय द्वारा मामले के गुण-दोष पर हस्तक्षेप करने और पक्षकारों द्वारा न्यायालय द्वारा मध्यस्थ की प्रारंभिक नियुक्ति को पहले ही स्वीकार करने के बाद, नियुक्ति प्राधिकरण नोटिस के बावजूद कार्य करने में विफल रहा है, यह माना जाएगा कि उसकी नियुक्ति के अधिकार का त्याग कर दिया गया है।

(41) नंद्याल कूप, स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में उच्चतम न्यायालय एक मध्यस्थता खंड से संबंधित था जिसमें कोई नामित मध्यस्थ नहीं था, लेकिन पक्षों के बीच विवादों को उस मामले में मालिक के प्रशासनिक प्रमुख द्वारा नियुक्त किए जाने वाले मध्यस्थ के मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने की आवश्यकता थी।इस तर्क को खारिज करते हुए कि एकमात्र मध्यस्थ को केवल अनुबंध के संदर्भ में नियुक्त किया जा सकता है और धारा 8 के तहत आवश्यक नोटिस दिए जाने के बावजूद न्यायालय को मध्यस्थ नियुक्त करने की कोई शक्ति नहीं है, न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया:—

> "यदि नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर अनुबंध के संदर्भ में कोई मध्यस्थ नियुक्त नहीं किया गया था, तो अपीलार्थी के प्रशासनिक प्रमुख ने अनुबंध के तहत मध्यस्थ नियुक्त करने की शक्ति का त्याग कर दिया था।अदालत को धारा 8 (1) (ए) के संचालन द्वारा अनुबंध के स्थान पर एक मध्यस्थ नियुक्त करने का अधिकार क्षेत्र प्राप्त होता है।इसलिए,
>
> यह तर्क कि चूंकि समझौते में अपीलार्थी के प्रशासनिक प्रमुख द्वारा नियुक्त मध्यस्थ को वरीयता दी गई है और यदि वह नियुक्त करने में लापरवाही करता है, तो ठेकेदार के लिए एकमात्र उपाय सिविल मुकदमे का सहारा लेना था।अनुबंध के तहत प्रत्यर्थी ने एक दीवानी अदालत द्वारा अपने दावे के निर्णय से अनुबंध किया।यदि एक नामित मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अनुबंध प्रदान किया गया था और नामित व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया गया था, तो निश्चित रूप से अनुबंध करने वाले पक्ष के लिए एकमात्र उपाय मुकदमा करने का अधिकार था।हाथ में ऐसा नहीं है।अनुबंध में एक नामित मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए स्पष्ट रूप से प्रावधान नहीं था।इसके बजाय अपीलार्थी के प्रशासनिक प्रमुख को एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करने की शक्ति दी गई थी।जब वह धारा 8 (1) (ए) के तहत निर्धारित 15 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर ऐसा करने में विफल रहा, तो प्रतिवादी को अनुबंध की शर्तों के तहत धारा 8 (1) (ए) के तहत उपचार का लाभ उठाने

का अधिकार दिया गया है और अदालत से एक मध्यस्थ नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है।"

(42) बेशक, पक्षकारों को मध्यस्थ के पक्षपात, बेईमानी या कदाचार के लिए मध्यस्थ की नियुक्ति पर सवाल उठाने की स्वतंत्रता होगी, लेकिन इस मामले के विशिष्ट तथ्यों को देखते हुए न्यायालय द्वारा उसकी नियुक्ति पर कानून के साथ-साथ रखरखाव के आधार पर भी शायद ही सवाल उठाया जा सकता है।

(43) मध्यस्थता कार्यवाही में पक्षों का आचरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है जिस पर न्यायालय द्वारा विचार किया जाना चाहिए।न्यायालय द्वारा क्रमिक मध्यस्थों की नियुक्ति की गई हो, जिसे पक्षकारों ने स्वेच्छा से स्वीकार किया हो या उक्त आदेशों को बहुत पहले अंतिमता प्राप्त हो गई हो, मध्यस्थ के समक्ष पक्षकारों की भागीदारी के साथ, आवेदन की स्थिरता या अन्यथा न्यायालय द्वारा ऐसे मध्यस्थों की नियुक्ति पर याचिका के संबंध में पूर्ण छूट के रूप में कार्य करेगा।भारत संघ और अन्य बनाम मैसर्स एलाइड कंस्ट्रक्शन कंपनी *(14)* के मामले में जहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय अनुबंध के उसी खंड 70 से संबंधित था और मध्यस्थ को न्यायालय द्वारा अधिनियम की धारा 8 और 20 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियुक्त किया गया था और उस आदेश को न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी कीः—

"विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश, बालासोर के 2 दिसंबर, 1976 के आदेश से ऐसा प्रतीत होता है, जिसकी उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है कि श्री बनबासी पटनायक राष्ट्रीय राजमार्ग मंडल, संबलपुर, उड़ीसा के अधीक्षण अभियंता हैं और एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी क्षमता और

सत्यनिष्ठा पर संदेह नहीं है।नाम का चयन विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा प्रतिवादी द्वारा तैयार किए गए नामों के एक पैनल से किया गया था, और अपीलकर्ताओं द्वारा इसमें कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई थी।इन परिस्थितियों में, हम कोई कारण नहीं देखते हैं कि श्री बनबासी पटनायक को मध्यस्थता में प्रवेश करने और दोनों मामलों में से प्रत्येक में अपना निर्णय देने की अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए।"

(44) मेसर्स एम. के. शाह बनाम मध्य प्रदेश राज्य *(15)* उच्चतम न्यायालय ने वर्तमान मामले में कुछ हद तक समान स्थिति के लिए अधिनियम के प्रावधानों की प्रयोज्यता पर कुछ विस्तार से चर्चा की।खंड 3.3.29 के तहत ठेकेदार द्वारा उठाए गए विवादों के संबंध में कुछ मदों पर अधीक्षण अभियंता का निर्णय अंतिम था, जो इस तरह के निर्णय से असंतुष्ट होने पर, उसे ज्ञात होने के 28 दिनों के भीतर मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए नोटिस दे सकता था।राज्य सरकार को समझौते के संदर्भ में पैनल से एक मध्यस्थ नियुक्त करने की आवश्यकता थी जिसका निर्णय अंतिम होना था। इस हाल के फैसले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पक्षकारों के आचरण और ऐसे मध्यस्थता खंडों के प्रभाव के संबंध में कुछ विस्तार से देखे गए कानून पर विचार करते हुए एक विशेष कार्य को निर्दिष्ट तरीके से करने का प्रावधान किया, जिसकी टिप्पणी नीचे दी गई है:—

"मध्यस्थता समझौतों में एक खंड हो सकता है जिसमें एक निश्चित अधिनियम को एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरा करने की आवश्यकता होती है और जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि वह कार्य नहीं किया जाता है तो दावा या मध्यस्थता शुरू करने की क्षमता पर रोक लगा दी जाएगी।खंड 3.3.29 के पूर्व भाग द्वारा बनाई गई रोक की याचिका, यदि कोई हो, को उस पक्ष द्वारा स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जो स्वयं इसके संचालन को विफल करने के लिए जिम्मेदार रहा है।यह न्याय का उपहास होगा यदि प्रतिवादीगण की गलती के लिए अपीलकर्ताओं को मध्यस्थता के उपचार का सहारा लेने के अधिकार से वंचित किया जाता है।"

"मध्यस्थता खंड के प्रवर्तन में आने से पहले के कदम हालांकि आवश्यक हैं, माफ किए जाने में सक्षम हैं और यदि एक पक्ष ने अपने स्वयं के आचरण या अपने अधिकारियों के आचरण से ऐसे पूर्ववर्ती कदम उठाए हैं, तो यह माना जाएगा कि प्रक्रियात्मक पूर्व-आवश्यकताओं को माफ कर दिया गया था।गलती करने वाले पक्ष को पूर्व-आवश्यक दायित्व के गैर-निष्पादन की सीमा स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है ताकि मध्यस्थता खंड की प्रयोज्यता और संचालन को बाहर रखा जा सके।"

"दोनों में मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए स्वेच्छा से सहमत होने में प्रतिवादीगण का बाद का आचरण

मामले और मध्यस्थता अधिनियम की धारा 33 के तहत उनकी आपत्तियों का पीछा नहीं करना खंड 3.3.29 के पहले भाग के गैर-अनुपालन के उनके अनुरोध की ओर से छूट के बराबर है, अगर केवल ऐसा गैर-अनुपालन था।निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने खंड 3.3.29 के पहले भाग का पालन न करने के आधार पर पुरस्कारों को रद्द करने और मध्यस्थ द्वारा नए सिरे से निर्णय के लिए उन्हें वापस भेजने में न्यायसंगत नहीं थे।"

(45) हम पहले ही न्यायालय द्वारा 30 मई, 1989 के अपने आदेश के अनुसार ब्रिगेडिर परिहार की नियुक्ति पर ध्यान दे चुके है। , जिसे किसी भी पक्ष द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी।भारत संघ की दलील है कि ब्रिगेडियर।परिहार को 25 मई, 1989 को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया था, जो मुख्य रूप से इस कारण से विश्वास को प्रेरित नहीं करता है कि भारत संघ ने न तो अपने जवाब में इस तरह के तथ्य का अनुरोध किया और न ही 25 मई, 1989 का कथित पत्र दर्ज किया।इसके विपरीत भारत संघ ने स्वयं 30 मई, 1989 को अधिनियम की धारा 8 के तहत एक आवेदन दायर किया जिसमें निचली अदालत से उक्त आवेदन के पैरा संख्या 3 में सुझाए गए पैनल में से एक मध्यस्थ नियुक्त करने का अनुरोध किया गया था।न्यायालय ने *29* मई, 1989 के अपने आदेश के अनुसार आवेदन स्वीकार कर लिया और 30 मई, 1989 के आदेश के अनुसार ब्रिगेडियर एम. एम. एस. परिहार एकमात्र मध्यस्थ के रूप मेंनियुक्त किया जिनका नाम निश्चित रूप से भारत संघ द्वारा सुझाए गए पैनल से बाहर था।फिर भी नियुक्ति एक न्यायालय द्वारा की गई नियुक्ति थी, न कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा।दावेदार कंपनी के आवेदन के निर्णय पर भारत संघ के अनुरोध पर विचार करने के बाद न्यायालय अब यह कहने के लिए वापस नहीं आ सकता है कि नियुक्ति न्यायालय द्वारा नहीं की गई थी जब वो ब्रिगेडियर परिहार के समक्ष न्यायालय द्वारा दिए गए समय पर न्यायालय के आदेश को आगे बढ़ाने के लिए पेश हुए।

(46) फिर भी, एक अन्य विकल्प के रूप में, दावेदार कंपनी की ओर से हमारे समक्ष यह तर्क दिया गया था कि श्री गुप्ता की मध्यस्थ के रूप में नियुक्ति से पहले ही विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन दायर किया गया था, जो इस संशोधन में हमारे सामने आक्षेपित है, प्रार्थना मध्यस्थ को रद्द करने या हटाने और एक स्वतंत्र व्यक्ति की नियुक्ति के लिए थी।इस संबंध में न्यायालय ने आवेदन को स्वीकार करने के बाद श्री वाधवा को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया था, आवेदन अधिनियम की धारा 11 के मूल अवयवों को संतुष्ट करता है और मध्यस्थ नियुक्त करने की शक्ति अधिनियम की धारा 12 के प्रावधानों के दायरे में आएगी।

(47) यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि किसी आवेदन का शीर्षक या किसी आवेदन का गलत तरीके से वर्णित शीर्षक, स्वयं उस आवेदन की रखरखाव क्षमता या अन्यथा के संबंध में उसके भाग्य का निर्धारण नहीं करता है।इस स्तर पर, दूसरे की सामग्री का संदर्भ दावेदार कंपनी की ओर से विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष दायर आवेदन आवश्यक होगा।हम पहले ही देख चुके हैं कि आवेदन में विशिष्ट कथन था कि ब्रिगेडियर।एम. एम. एस. परिहार ने कानून के अनुसार कार्रवाई करने या प्रवेश करने और संदर्भ के साथ आगे बढ़ने की उपेक्षा की थी और निर्धारित अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी थी।एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए विशिष्ट प्रार्थना की गई थी। इस आवेदन को भारत संघ द्वारा चुनौती दी गई थी, लेकिन अंततः योग्यता के साथ-साथ ब्रिगेडियर परिहार ने 15 दिसंबर, 1990 को इस्तीफा दे दिया के कारण इसकी अनुमति दी गई थी।

(48) श्री बी. के. वाधवा को तब मध्यस्थ नियुक्त किया गया था।उनकी नियुक्ति को भारत संघ द्वारा उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, लेकिन उसके द्वारा दायर संशोधन को खारिज कर दिया गया था।जिस मूल आदेश को देखते हुए भारत संघ द्वारा दायर नागरिक संशोधन को खारिज कर दिया गया था, वह उसी तारीख 1991 के नागरिक संशोधन संख्या 1220 में पारित आदेश पर आधारित था, यानी 9 जुलाई, 1993 और भारत संघ द्वारा डाली गई विशेष अनुमति याचिका को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिक पुनरीक्षण संख्या 1220 14 जुलाई, 1994 को 1991 का J.220 के ख़िलाफ़ ख़ारिज कर दिया।

(49) अभिलेख से यह स्पष्ट है कि दावेदार कंपनी द्वारा विभिन्न अवसरों पर इस आशय की मांग की सूचना के बावजूद भारत संघ नियुक्तियां करने में विफल रहा।नियुक्त मध्यस्थों ने या तो इस्तीफा दे दिया या कार्रवाई करने में विफल रहे।यूनियन ऑफ इंडिया दावेदार कंपनी को अनुचित देरी और मध्यस्थता कार्यवाही में बाधा डालने के लिए दोषी ठहराती है, जबकि दावेदार कंपनी अपनी चूक और आयोगों द्वारा जानबूझकर मध्यस्थता कार्यवाही में बाधा डालने में यूनियन ऑफ इंडिया के आचरण की निंदा करती है।इस देरी के लिए जो कोई भी जिम्मेदार हो, रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि श्री गुप्ता को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किए जाने तक कोई प्रभावी मध्यस्थता कार्यवाही नहीं की गई थी-5 अप्रैल, 1994 के आदेश के अनुसार और उन्होंने 27 अगस्त, 1996 को अपना निर्णय दिया। दूसरे शब्दों में, 1969 से 1994 तक किसी भी नियुक्त मध्यस्थ द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई थी।

(50) हम श्री गुप्ता को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने में विद्वत विचारण न्यायालय के आदेश में अधिकार क्षेत्र की कोई त्रुटि नहीं देख पा रहे हैं।अधिनियम की धारा 11 के तहत निर्धारित आधारों को विशेष रूप से मध्यस्थ को हटाने के लिए अनुरोध किया गया था क्योंकि वह संदर्भ के साथ प्रवेश करने और आगे बढ़ने और निर्णय देने में सभी उचित प्रेषण का उपयोग करने में विफल रहा।मध्यस्थ इस अधिनियम के तहत इतने शक्तिहीन नहीं हैं कि विवाद का कोई भी पक्ष मध्यस्थ द्वारा संदर्भ के उद्देश्य और इसके निर्धारण को विफल कर सकता है।हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई संकोच नहीं है कि वैकल्पिक रूप से आवेदन को अधिनियम की धारा 11 के तहत एक आवेदन के रूप में माना जा सकता है और न्यायालय के मध्यस्थ की नियुक्ति का परिणामी आदेश था

अधिनियम की धारा 12 के तहत प्रदान किए गए कानून के चार कोनों और इसके अधिकार क्षेत्र के भीतर पारित किया गया।

(51) उपरोक्त चर्चा और इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारा दृढ़ विचार है कि अधिनियम की धारा 8 के तहत आवेदन बनाए रखने योग्य था, भारत संघ ने अपने आचरण द्वारा या अन्यथा इसकी बनाए रखने और नियुक्ति पर आपत्ति को त्याग कर दिया, यदि कोई हो; और, किसी भी स्थिति में आवेदन को धारा 11 के तहत एक आवेदन के रूप में माना जा सकता है।वह कार्य करता है। इस तरह हम ऊपर बताए गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं।

(52) भारत संघ की ओर से कुछ जोर देते हुए विद्वान वकील ने तर्क दिया कि मेसर्स हरबंस सिंह तुली एंड संस बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड को वर्तमान पुनरीक्षण याचिका सहित अब तक दायर की गई किसी भी याचिका को दायर करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यह पक्षों के बीच मध्यस्थता खंड वाले अनुबंध के लिए अजनबी है।इस तथ्य पर जोर दिया गया कि अनुबंध सं। 69-70 के CENWZ/AMB-24 को मेसर्स हरबंस सिंह तुली एंड संस के एकमात्र मालिक श्री एच. एस. तुली के बीच निष्पादित किया गया था, जिनकी वर्ष 1982 में मृत्यु हो गई थी और रिकॉर्ड पर उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना, वर्तमान कंपनी पर मृतक की ओर से कार्यवाही नहीं की जा सकती थी।

(53) भारत संघ की ओर से उठाया गया यह तर्क न केवल असराहीनय है, बल्कि बहुत देर से उठाया गया है।यह सच है कि मूल समझौता, 69-70 का अनुबंध संख्या 24 होने के कारण, मृतक श्री तुली और भारत संघ के बीच एकमात्र मालिक के रूप में निष्पादित किया गया था।श्री तुली ने कहा कि छह कानूनी प्रतिनिधियों को पीछे छोड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई।कंपनी की ओर से यह दावा किया जाता है कि इन कानूनी प्रतिनिधियों ने विद्वत निचली अदालत के समक्ष आवेदन दायर किए थे।न्यायालय द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 8 के तहत पहले आवेदन में 24 मार्च, 1988 को प्रतिवादीगण को नोटिस दिया गया था और उपरोक्त कंपनी को कानूनी प्रतिनिधियों के रूप में रिकॉर्ड में लाने के लिए सहमत अन्य कानूनी प्रतिनिधियों के शपथ पत्र सहित सभी दस्तावेज भी दायर किए गए थे।जून, 1982 में श्री तुली की मृत्यु के बाद, विभिन्न कार्यवाहियां हुईं जहाँ भारत संघ ने स्वयं कंपनी के अधिकार को स्वीकार किया है और कार्यवाही में

एकमात्र प्रतिवादी के रूप में कंपनी को स्वयं ही लागू किया है।इन सभी दस्तावेजों को भारत संघ द्वारा नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ श्री पी. डी. गुजराती के समक्ष 27 अगस्त, 1984 के न्यायालय के आदेश के साथ भारत संघ को भी दिया गया था।कंपनी ने निचली अदालत के समक्ष दायर अपने आवेदन में आवेदन के पैराग्राफ 2 में विशेष रूप से कहा था कि कंपनी ने मृतक श्री तुली की सभी संपत्तियों और एकल स्वामित्व चिंता के दायित्व को अपने हाथ में ले लिया था और इस तरह से सक्षम था

उन कार्यवाहियों का अनुसरण करें जिन पर भारत संघ द्वारा कोई आपत्ति नहीं ली गई थी, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है।विद्वत विचारण न्यायालय ने 19 फरवरी, 1983 के अपने आदेश के माध्यम से मेसर्स हरबंस सिंह तुली एंड संस बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड को मेसर्स हरबंस सिंह तुली एंड संस के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में दर्ज किया।कंपनी की ओर से दायर आवेदन के पैराग्राफ 2 में कहा गया थाः—

> *"2.* वह एस। इस कंपनी के एकमात्र मालिक हरबंस सिंह तुली का 16 जून, 1982 को न्यूयॉर्क (यू. एस. ए.) में निधन हो गया और वे निम्नलिखित कानूनी उत्तराधिकारियों को पीछे छोड़ गएः—
>
> | | | |
> |---|---|---|
> | ((i) | श्रीमती. प्रकाश कौर तुली | विधवा। |
> | ((ख) | एस. बलबीर सिंह तुली | बेटा। |
> | (iii) | एस. लखबीर सिंह तुली | बेटा। |
> | ((iv) | एस. हरकिशन सिंह तुली | बेटा। |
> | (v) | डॉ. रानी बलबीर कौर | बेटी। |
> | (vi) | एस. बालकृष्ण सिंह तुली | बेटा। |
>
> उक्त श्री की मृत्यु पर। हरबंस सिंह तुली ने कहा कि सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को उपरोक्त छह कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा उत्तराधिकारी और विरासत में प्राप्त किया गया था, जो प्रतिवादी से सभी बकाया और हर्जाने की वसूली के हकदार बन गए थे, लेकिन उपरोक्त सभी कानूनी उत्तराधिकारियों ने सर्वसम्मति से फैसला किया और याचिकाकर्ता-कंपनी ने सभी कानूनी उत्तराधिकारियों की सभी संपत्तियों और देनदारियों को अपने हाथ में ले लिया जो उन्हें श्री की मृत्यु पर विरासत में मिली हैं। मेसर्स हरबंस सिंह तुली एंड संस के संबंध में हरबंस सिंह तुली।"

(54) इस आवेदन का कोई जवाब नहीं दिया गया।हालाँकि, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 के तहत भारत संघ की ओर से 1989 के मामले संख्या 20 में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें आवेदन में सुझाए गए पैनल से मध्यस्थ के न्यायालय द्वारा नियुक्ति का अनुरोध किया गया था।इन दोनों आवेदनों का निपटारा विद्वत निचली अदालत ने क्रमशः 29 मई, *1989* और 30 मई, 1989 के आदेश के माध्यम से किया था।उक्त आदेशों को पक्षों के बीच अंतिम रूप मिल गया था। श्री तुली की मृत्यु के बाद वर्ष 1982 से ही कंपनी इस मामले पर मुकदमा चला रही है और भारत संघ ने अपनी दलीलों के साथ-साथ अपने आचरण से इस तथ्य को पूरी तरह से स्वीकार किया है कि कंपनी कानूनी रूप से अपनी पूरी देनदारियों और लाभों को लेकर मृतक की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करने की हकदार है।

(55) हमारे लिए, ऐसा प्रतीत होता है कि कंपनी के अधिकार क्षेत्र के संबंध में भारत संघ की आपत्ति आधारहीन है।दस्तावेज़, जो तय किए गए नागरिक पुनरीक्षण के अभिलेख पर उपलब्ध हैं

हमारे समक्ष सुनवाई के लिए और अन्य संबंधित मामलों से पता चलता है कि-10 मई, 1989 और 25 मई, 1989 को कार्यवाहक मुख्य अभियंता ने उनके द्वारा लिखे गये पत्रों के माध्यम से श्री ए. जे. कुआनरेसन और ब्रिगेडियर एम.एम एस परिहार को क्रमशः निम्नलिखित पाठों पर मध्यस्थ के रूप में नियुक्त कियाः—

"और जहाँ विवाद अभी भी बने हुए हैं।

और जहाँ मेसर्स हरबंस सिंह तुली एंड संस बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड ने मेसर्स हरबंस सिंह तुली एंड संस की सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को अपने हाथ में ले लिया है।

(56) भारत संघ के वकील ने यह तर्क देते हुए लाभ प्राप्त करने की कोशिश की कि उपरोक्त पत्र इंजीनियर-इन-चीफ और भारत संघ द्वारा लिखा गया था न कि समझौते के किसी पक्ष द्वारा, क्योंकि इसे भारत संघ के प्रवेश के रूप में नहीं माना जा सकता है।यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि प्रक्रियात्मक कानून के साक्ष्य का सख्त नियम मध्यस्थता की कार्यवाही में आकर्षित नहीं होता है।हमारे सामने यह विवादित नहीं है कि इंजीनियर-इन-चीफ वर्तमान अनुबंध के मुख्य इंजीनियर पक्ष सहित विभिन्न मुख्य इंजीनियरों के विभाग का प्रमुख है।ये दोनों अधिकारी और कुछ नहीं बल्कि भारत संघ के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के तहत काम करने वाले पदानुक्रम के व्यक्ति हैं। भारत संघ आपत्ति उठाने में विफल रहा और दूसरी ओर इस पूरी अवधि के लिए कंपनी के रुख को विशेष रूप से स्वीकार करने के बाद, अदालत के लिए भी चीजों को अस्थिर करना अनुचित होगा ताकि वे इस दृष्टिकोण पर 30 साल पहले लौट आएं।

(57) 1994 के सिविल पुनरीक्षण सं. 1685 और उस मामले के लिए भारत संघ द्वारा पसंद किए गए अन्य पुनरीक्षणों के लिए, दिलचस्प बात यह है कि भारत संघ ने स्वयं इन सभी संशोधनों में मैसर्स एच. एस. तुली एंड संस बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड को एकमात्र प्रतिवादी के रूप में शामिल किया है।न तो वनों से भरे तथ्यों पर कोई विवाद है और न ही हमारे सामने कोई विवाद उठाया गया है।हमारा विचार है कि भारत संघ अपनी आपत्तियों को कायम नहीं रख सकता है।लगभग 2 वर्ष से अधिक के अंतराल के बाद इस तरह के विलंबित चरण में आपत्ति उठाते हुए, हम भारत संघ के नुकसान के लिए भी विबंध और अनुकूलता के सिद्धांत को लागू नहीं करने का कोई कारण नहीं पाते हैं।

(58) इस स्तर पर, मध्यस्थता अधिनियम के तहत विषय को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों को संदर्भित करना उचित हो सकता है। अधिनियम की धारा 2 (डी) के तहत 'कानूनी प्रतिनिधि' शब्द को परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो कानूनी रूप से मृतक व्यक्ति की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है और जिसमें कोई भी व्यक्ति शामिल है जो मृतक की संपत्ति के साथ घुलमिल जाता है।अधिनियम की धारा 6 में विधायी अधिदेश है कि समझौते का निर्वहन किसी भी पक्ष की मृत्यु से नहीं किया जाएगा, लेकिन यह आवश्यक है कि

मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा या उनके खिलाफ लागू किया जा सकता है।यहां तक कि मध्यस्थ का अधिकार भी उस पक्ष द्वारा निरस्त नहीं किया जाएगा जिसके द्वारा उसे नियुक्त किया गया था। इन प्रावधानों के संचयी अध्ययन पर, हम कोई कारण नहीं देखते हैं कि कंपनी के पास कार्यवाही जारी रखने का कोई अधिकार क्यों नहीं है।मध्यस्थ के साथ-साथ विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष कंपनी द्वारा किए गए कथन निर्विवाद रहे और रिकॉर्ड पर वर्तमान कानूनी प्रतिनिधियों के संबंध में उस पर आदेश अप्रमाणित रूप से पारित किया गया।विधायी आशय 'कानूनी प्रतिनिधि' अभिव्यक्ति को उदार निर्माण प्रदान करता प्रतीत होता है और इस तरह के याचिका पर उसे निराश करने के बजाय मध्यस्थता कार्यवाही के निष्कर्ष को सुनिश्चित करता है।मध्यस्थता कार्यवाही मुख्य रूप से पक्षों की पारस्परिकता पर आधारित होती है और पक्षकारों ने संपत्ति के संबंध में स्थिति को स्वीकार कर लिया है, न्यायालय इस तरह की पारस्परिकता को बाधित करने में कम से कम उचित होगा और किसी भी मामले में कार्यवाही के इस अंतिम चरण में।पार्टी के अधिकार क्षेत्र के संबंध में आपत्ति मुख्य रूप से एक पार्टी के लिए उपलब्ध है और इसे माफ किया जा सकता है।यह न्यायालय के न्यायसंगत अधिकार क्षेत्र या अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र की कमी का मामला नहीं है।भारत संघ ने अपने पूरे विवेक के साथ न केवल आपत्ति को माफ कर दिया था, बल्कि निश्चित अभिवचन के साथ कंपनी को मृतक के उचित उत्तराधिकारी के रूप में विशेष रूप से स्वीकार किया था कि कंपनी ने मृतक की सभी संपत्तियों और दायित्वों को ले लिया था।इसलिए, हम भारत संघ की ओर से उठाए

गए इस विवाद में योग्यता के किसी भी तत्व का पता लगाने में असमर्थ हैं।

(59) दावेदार कंपनी की ओर से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित श्री तुली ने तर्क दिया है कि उच्च न्यायालय ने विभिन्न अवसरों पर मध्यस्थ द्वारा निर्णय देने के लिए समय बढ़ाया था और इस तरह इस न्यायालय ने मध्यस्थता कार्यवाही पर अपना नियंत्रण बनाए रखा था।इस प्रकार, उच्च न्यायालय सक्षम अधिकार क्षेत्र का न्यायालय होगा जहाँ मध्यस्थ को निर्णय दाखिल करना चाहिए। दूसरी ओर, भारत संघ की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि विद्वत विचारण न्यायालय सक्षम अधिकार क्षेत्र का न्यायालय होने के नाते और जिसने मध्यस्थों की नियुक्ति सहित मध्यस्थों के समक्ष कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान विभिन्न आदेश पारित किए थे, सक्षम अधिकार क्षेत्र का एकमात्र न्यायालय है।

(60) इस प्रश्न का उत्तर देने के प्रयोजनों के लिए मध्यस्थता अधिनियम की धारा 2 (सी), 14,28 और 31 को एक साथ पढ़ना होगा।इन प्रावधानों के संचयी पठन पर यह स्पष्ट है कि इस अधिनियम के तहत न्यायालय का अर्थ है सिविल न्यायालय जिसे संदर्भ की विषय वस्तु बनाने वाले प्रश्न का निर्णय करने का अधिकार क्षेत्र है, यदि उसके पास इस तरह के मुकदमे का निर्णय करने का अधिकार क्षेत्र था।धारा 14 के तहत न्यायालय का पंचाट नियम बनाने के लिए न्यायालय में निर्णय दायर करना पड़ता है।

धारा 28 के प्रावधानों के भीतर न्यायालय के पास अधिनिर्णय देने के लिए समय बढ़ाने का अधिकार क्षेत्र है।धारा 31 वह धारा है जो अधिनियम के अन्य प्रावधानों में निर्दिष्ट न्यायालय की अधिकारिता को नियंत्रित करती है। धारा 31 की उप-धारा (1) के तहत उस मामले में अधिकारिता रखने वाले किसी भी न्यायालय में एक निर्णय दायर किया जा सकता है जिससे संदर्भ संबंधित है।उप-धारा (2) एक गैर-अस्थाई खंड है जो यह प्रावधान करता है कि पक्षकारों के बीच किसी समझौते की वैधता, प्रभाव या विस्तार या मध्यस्थता के संबंध में सभी प्रश्नों का निर्णय उस न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसमें पंचाट दायर किया गया है या दायर किया जा सकता है और आगे यह प्रतिबंध लगाता है कि कोई अन्य न्यायालय उस ओर से अधिकारिता नहीं लेगा।उप-धारा (3) के तहत मध्यस्थता कार्यवाही के संचालन के संबंध में सभी आवेदन उस न्यायालय में किए जाने चाहिए जहां पंचाट दिया गया है या दायर किया जा सकता है और फिर से किसी अन्य न्यायालय को ऐसे मामलों पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से प्रतिबंधित करता है।धारा 31 की उप-धारा (4) एक बहुत ही भौतिक प्रावधान है। उक्त उप-धारा में फिर से एक गैर-अस्थाई खंड शामिल है और साथ ही किसी अन्य न्यायालय पर ऐसे मामलों पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से प्रतिबंध लगाता है।यह स्पष्ट रूप से कहता है "जहां किसी भी संदर्भ में इस अधिनियम के तहत कोई आवेदन किसी न्यायालय में किया गया है, जो इसे स्वीकार करने के लिए सक्षम है, कि अकेले न्यायालय के पास मध्यस्थता कार्यवाही पर अधिकार क्षेत्र होगा और उस संदर्भ से उत्पन्न होने वाले सभी बाद के आवेदन और मध्यस्थता कार्यवाही उस न्यायालय में और किसी अन्य न्यायालय में नहीं की जाएगी।"

(हमारे द्वारा ज़ोर प्रदान किया गया)

(61) सामान्य तौर पर सभी कार्यवाहियों को उसी न्यायल्य में होना होगा जिसने शुरू में मध्यस्थ की नियुक्ति की थी या प्रारंभिक चरण में संदर्भ के विषय से निपटा था।यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि समय के विस्तार के साथ-साथ निर्णय दाखिल करने और मध्यस्थता कार्यवाही पर नियंत्रण के संबंध में बाद के आवेदनों को उस न्यायालय में दायर किया जाना चाहिए और बनाए रखा जाना चाहिए जिसके समक्ष शुरू में मध्यस्थता समझौते और विषय वस्तु के संबंध में कार्यवाही शुरू की गई थी।संदर्भ की विषय वस्तु पर विचार करने के लिए सक्षम न्यायालय धारा 2 (सी) के तहत परिभाषित न्यायालय होगा, जैसा कि पहले से ही एक दीवानी न्यायालय को संदर्भ की विषय वस्तु पर अधिकारिता रखते हुए देखा गया है, यदि वही वाद का विषय था।दूसरे शब्दों में, धारा 31 'न्यायालय' की उप-धारा (4) के तहत सिविल न्यायालय होगा जो अधिनियम के तहत मध्यस्थता कार्यवाही में संदर्भ विषय की प्रकृति के मुकदमे का परीक्षण करने के लिए अधिकार क्षेत्र और सक्षम होगा। इस प्रकार, हमारे लिए सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 15 के प्रावधानों का उल्लेख करना

आवश्यक हो जाता है, जो निम्नानुसार हैः—

" 15 जिस न्यायालय में वाद स्थापित किए जाने हैं-प्रत्येक वाद निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में स्थापित किया जाएगा जो इसे चलाने के लिए सक्षम होगा।

(62) केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में निम्नतम श्रेणी के न्यायालय के पास किसी भी मूल्य के मुकदमों या याचिकाओं पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है।जबकि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 15 जो मुकदमा करने के स्थान का वर्णन करती है, "इसे चलाने के लिए सक्षम निम्नतम श्रेणी के न्यायालय" को संदर्भित करती है और मध्यस्थता अधिनियम की धारा 31 (4) अधिनियम के तहत दायर किसी भी आवेदन को स्वीकार करने के लिए सक्षम न्यायालय को संदर्भित करती है। उपरोक्त प्रावधानों को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करने के लिए कार्यवाही के प्रारंभिक चरण में संबंधित पक्षों द्वारा दायर किए गए विभिन्न आवेदनों का संदर्भ अपरिहार्य होगा।हमारे समक्ष इन संशोधनों में विवादित आदेश के पारित होने से पहले पक्षों द्वारा कुछ अन्य समान आवेदन दायर किए गए थे जो अंततः सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय द्वारा निपटाए गए थे और पक्षों के बीच अंतिमता प्राप्त कर चुके हैं।

पहला अनुप्रयोगः

(63) मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 के तहत कंपनी की ओर से एक आवेदन दायर किया गया था जिसमें अनुरोध किया गया था कि प्रतिवादीगण श्री पी. डी. गुजराती, एकमात्र मध्यस्थ द्वारा नियुक्त मध्यस्थ ने 8 मार्च, 1988 को इस्तीफा दे दिया था और 24 मार्च, 1988 के नोटिस के बावजूद प्रतिवादीगण मध्यस्थ की नियुक्ति करने में विफल रहे थे।और इस प्रकार, अदालत द्वारा रिक्ति की आपूर्ति के लिए आवेदन कंपनी द्वारा दायर किया गया था।यह आवेदन दिनांक 25 फरवरी, 1989 का है और 27 फरवरी, 1989 को एक मुकदमे के रूप में दर्ज किया गया था।विद्वान उप न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, चंडीगढ़ ने 29 मई, 1989 के आदेश के माध्यम से अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 के तहत एक मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए पूरी तरह से सक्षम था और उक्त आवेदन को अनुमति दी और मामले को 30 मई, 1989 के लिए निर्धारित किया।30 मई, 1989 को भारत संघ ने स्वयं मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 के तहत एक आवेदन दायर किया जिसमें प्रार्थना की गई कि मुख्य अभियंता को एक मध्यस्थ नियुक्त करने की अनुमति दी जाए और वैकल्पिक मध्यस्थ को न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन के अनुच्छेद संख्या 3 में सुझाए गए मध्यस्थों के पैनल से नियुक्त किया जाए।इस प्रकार, याचिकाकर्ता के साथ-साथ भारत संघ के आवेदन का अंत में निपटारा कर दिया गया-30 मई, 1989 के आदेश के माध्यम से जहां न्यायालय ने ब्रिगेडियर एम . एम. एस. परिहार को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया। आदेश का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः—

> "पक्षकारों के वकील को सुनने के बाद, मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि यद्यपि न्यायालय न्याय के हित को ध्यान में रखते हुए और पक्षकारों के बीच विवाद पर शीघ्र निर्णय लेने के लिए और दावा पुरस्कार की राशि को ध्यान में रखते हुए, किसी भी पक्षकार द्वारा दी गई सूची में से मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए बाध्य नहीं है, मैं ब्रिगेडियर एम.एम परिहार को अनुबंध समझौते सं. के विरुद्ध याचिकाकर्ता के दावे के संबंध में। 69-70 "का CENWZ/AMB-24 का निर्णय लेने के लिये नियुक्त करता हूँ।

(64) भारत संघ ने अपील या पुनरीक्षण में किसी भी उच्च न्यायालय के समक्ष उक्त आदेश पर हमला नहीं किया और उक्त आदेश ने पक्षों के बीच अंतिमता प्राप्त की।एक अन्य तथ्य जिसे इस स्तर पर स्पष्ट करने की आवश्यकता है, वह यह है कि भारत संघ ने 25 मई 1989 के अपने पत्र के माध्यम से ब्रिगेडियर परिहार एकमात्र मध्यस्त के रूप में नियुक्त करने का दावा किया है हलांकि, इस पत्र का उल्लेख न तो भारत संघ द्वारा 30 मई, 1989 को विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष दायर आवेदन में किया गया था और न ही उक्त पत्र की प्रति को कभी देखा गया वर्तमान संशोधन तक इस न्यायालय द्वारा सुनवाई की जा रही थी।

दूसरा अनुप्रयोगः

(65) 17 अक्टूबर, 1989 को कंपनी ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 के तहत एक और आवेदन दायर किया। आवेदन में कहा गया था कि ब्रिगेडियर।एम. एम. एस. परिहार को मध्यस्थता के दावों पर निर्णय लेने के लिए मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया था-न्यायालय द्वारा 30 मई, 1989 के आदेश के अनुसार, लेकिन ब्रिगेडियर ने कहा।परिहार ने अदालत के आदेश के अनुसार कार्रवाई करने, प्रवेश करने और संदर्भ के साथ आगे बढ़ने की उपेक्षा की थी।उक्त मध्यस्थ के भारत संघ में कार्यरत होने के पूर्वाग्रह के संबंध में आवेदन में अन्य अभिकथन भी किए गए थे और इस प्रकार, न्यायालय के समक्ष प्रार्थना की गई थी कि ब्रिगेडियर परिहार को निरस्त किया जाए और एक स्वतंत्र मध्यस्थ नियुक्त किया जाए।

(66) भारत संघ ने इस आवेदन का जवाब दायर कर याचिकाकर्ता पर ब्रिगेडियर के समक्ष उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जमा नहीं करने का आरोप लगाया।परिहार ने दलील दी कि देरी याचिकाकर्ता के कारण हुई थी।यह कहा गया था कि कार्यवाही याचिकाकर्ता द्वारा स्वयं बाधित की गई थी और वह अपनी गलतियों का लाभ नहीं उठा सकता था।

(67) यह जवाब 12 जून, 1990 को दायर किया गया था और अदालत द्वारा 16 फरवरी, 1991 के अपने आदेश के अनुसार आवेदन का अंत में निपटारा कर दिया गया था।अदालत ने तैयार किए गए मुद्दों पर अपने निष्कर्ष को दर्ज किया और अंततः पाया कि कंपनी के दावों पर पिछले 19-20 वर्षों से निर्णय नहीं लिया जा रहा था और ब्रिगेडियर परिहार की ओर से निष्क्रियता का भी उल्लेख किया। हालांकि, इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि ब्रिगेडियर।परिहार ने 15 दिसंबर, 1990 को इस्तीफा दे दिया था और अदालत ने कहा थाः—

> "मध्यस्थ को हटाने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा दायर पहले के आवेदन को खारिज कर दिया गया था, लेकिन अब चूंकि मध्यस्थ ने 15 दिसंबर, 1990 को इस्तीफा दे दिया है और इसलिए याचिकाकर्ता के दावों पर निर्णय लेने में असमर्थ हो गया है, और चार महीने से अधिक की अवधि समाप्त हो गई है।

और मध्यस्थ ने निर्णय की घोषणा नहीं की है और इसलिए, मेरे पास याचिकाकर्ता को उसके स्थान पर नए मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवेदन करने की अनुमति देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।"

"पूर्वगामी कारणों से, याचिका को लागत के साथ स्वीकार किया जाता है और मैं श्री को बी. के. वाधवा, मुख्य अभियंता, भवन, लोक निर्माण विभाग, हरियाणा, याचिकाकर्ता के दावों पर निर्णय लेने के लिए मध्यस्थ के रूप में, यदि कोई हो, और संदर्भ पर प्रवेश करने की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर पुरस्कार की घोषणा करने के लिए नियुक्त किया है।

(68) 16 फरवरी, 1991 के विद्वत विचारण न्यायालय के आदेश को 1991 के सिविल पुनरीक्षण संख्या 1245 में चुनौती दी गई थी।भारत संघ द्वारा दायर इस संशोधन को उच्च न्यायालय ने 9 जुलाई, 1993 के अपने आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया था।वास्तव में पुनरीक्षण को उसी पक्षकारों के बीच एक अन्य मामले में न्यायालय द्वारा पारित आदेश के संदर्भ में खारिज कर दिया गया था, जिसमें एक ही प्रश्न शामिल था, लेकिन समान खंडों के साथ एक अलग अनुबंध से संबंधित था।इसे 1991 के सिविल पुनरीक्षण संख्या 1221 के रूप में पंजीकृत किया गया था और वर्तमान पुनरीक्षण में कंपनी द्वारा दायर समय बढ़ाने के आवेदन के साथ-साथ धारा 8 के तहत आदेश के खिलाफ मुख्य याचिका को सिविल विविध संख्या न 3558 /सी -II और 1991 का सिविल पुनरीक्षण स 1220 में पारित आदेश के संदर्भ में खारिज कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने केवल निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा।

(69) उच्च न्यायालय द्वारा 1991 के सिविल पुनरीक्षण संख्या 1220 में पारित आदेशों के संदर्भ में निचली अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय द्वारा 9 जुलाई, 1993 के अपने आदेश के अनुसार स्थगित कर दिया गया था।1991 के सिविल संशोधन सं. 1220 के आदेश को उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी और 1994 के अपील करने के लिए विशेष अनुमति सं. 1139 को 14 जुलाई, 1994 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था।

क्या उच्च न्यायालय ने मध्यस्थता कार्यवाही पर अपना नियंत्रण बनाए रखा या उसे बनाए रखना चाहिए?

(70) कंपनी की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि उच्च न्यायालय ने विभिन्न आदेश पारित किए थे और विशेष रूप से 9 जुलाई, 1993 का आदेश एक अन्य विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया था और मध्यस्थता कार्यवाही पर अपना नियंत्रण बनाए रखा था।दावेदार कंपनी ने 1994 के सिविल पुनरीक्षण संख्या 1685 में भी एक आवेदन दायर किया है जिसमें अनुरोध किया गया है कि उच्च न्यायालय को आवेदन में बताए गए कारणों से मध्यस्थता कार्यवाही पर नियंत्रण बनाए रखना चाहिए।दूसरी ओर, भारत संघ की ओर से पेश वकील के अनुसार, उच्च न्यायालय ने वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मध्यस्थता कार्यवाही पर कभी भी नियंत्रण नहीं रखा और न ही उसे बनाए रखना चाहिए।

(71) अक्सर प्रतिद्वंद्वी विवादों की सराहना करने के लिए!इस संबंध में पक्षकारों को, हमें दो अलग-अलग उप-शीर्षों के तहत पूरे विवाद की जांच करनी होगीः—

(a) क्या माननीय न्यायमूर्ति श्री वी. के. बाली द्वारा दिनांक 9 जुलाई, 1993 को पारित आदेश मध्यस्थता कार्यवाही पर इस न्यायालय का नियंत्रण बनाए रखने के समान है या नहीं?

(b) हालाँकि, आवेदन में बताए गए कारणों से इस न्यायालय को 1994 की सिविल पुनरीक्षण संख्या 1685 दाखिल करने के बाद मध्यस्थता कार्यवाही पर नियंत्रण बनाए रखना चाहिए या नहीं?

(72) यह तर्क दिया जाता है कि समय बढ़ाने का आदेश पारित करते हुए और एकमात्र मध्यस्थ को फिर से निर्देश देने का निर्देश देते हुए, उच्च न्यायालय ने 9 जुलाई, 1993 के अपने आदेश के माध्यम से मध्यस्थता कार्यवाही पर नियंत्रण बनाए रखने का इरादा किया था।

(73) निर्विवाद तथ्य यह है कि 16 फरवरी, 1991 को श्री बी. के. वाधवा को न्यायालय द्वारा मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्होंने 18 मार्च, 1991 को निर्देश दिया था।16 फरवरी, 1991 के न्यायालय के आदेश को भारत संघ द्वारा 11 अप्रैल, 1991 को दायर 1991 के सिविल पुनरीक्षण संख्या 1245 में चुनौती दी गई थी।उच्च न्यायालय ने अपने *12* अप्रैल, 1991 के आदेश में निम्नलिखित आदेश पारित किया थाः—

"23 अप्रैल, 1991 के लिए प्रस्ताव की सूचना।इस स्तर पर अधिवक्ता श्री सलिल सागर प्रतिवादी की ओर से नोटिस स्वीकार करते हैं।तर्क के लिए उपरोक्त तिथि पर आना।

इस बीच, मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है, लेकिन दावेदार, हालांकि, अपना दावा कर सकते हैं।सी. आर. 1221/91 के साथ सुना जाना।"

(74) इस याचिका के लंबित रहने के दौरान, सिविल विविध।1993 का सं. 3559 भी दावेदार कंपनी द्वारा दायर किया गया था जिसमें मध्यस्थ को अपना निर्णय सुनाने के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध किया गया था।भारत संघ द्वारा 9 जुलाई, 1993 को दायर 1991 के सिविल पुनरीक्षण संख्या 1245 के आदेश को 1991 के सिविल पुनरीक्षण संख्या 1220 में पारित आदेशों के संदर्भ में खारिज कर दिया गया था, जबकि समय बढ़ाने के लिए दावेदार कंपनी द्वारा दायर विविध आवेदन की अनुमति दी गई थी।उच्च न्यायालय ने उक्त आवेदन को स्वीकार करते हुए निर्देश दिया -

"ऊपर दिए गए अनियंत्रित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, इस विविध आवेदन की अनुमति दी जाती है और 1991 का सिविल संशोधन संख्या 1220 खारिज कर दिया जाता है। पुरस्कार देने का समय

निम्नलिखित न्यायालय द्वारा नियुक्त मध्यस्थ को उस तारीख से चार महीने के लिए बढ़ाया जाता है जब वह फिर से संदर्भ दर्ज करता है।" (हमारे द्वारा प्रदान किया गया)

(75) उपरोक्त तथ्यों के आलोक में, हमें इस बात पर विचार करना होगा कि क्या उपरोक्त आदेश केवल एक परिणामी आदेश था या एक आदेश था जो पक्षों के बीच मध्यस्थता कार्यवाही पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए न्यायालय के विशिष्ट इरादे को व्यक्त करता था।हमारे लिए, यह प्रतीत होता है कि न्यायालय का आदेश केवल एक आदेश का सूचक है जो कार्यवाही के समापन पर पारित परिणामी आदेश की प्रकृति में है।प्रतिवादी को सिविल पुनरीक्षण का नोटिस जारी करते हुए, न्यायालय ने मध्यस्थ के समक्ष आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।पुनरीक्षण याचिका खारिज होने से पहले, चार महीने की निर्धारित अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी थी।याचिका को खारिज

करते समय न्यायालय को मध्यस्थता कार्यवाही को आगे जारी रखने के संबंध में रोक को रद्द करते हुए एक संशोधन देना पड़ा।"संदर्भ पर फिर से दर्ज करें" अभिव्यक्ति का सीधा संबंध 12 अप्रैल, 1991 के न्यायालय के आदेश से है।न्यायालय ने उच्च न्यायालय के नियंत्रण का संकेत देते हुए मध्यस्थता कार्यवाही को जारी रखने और जारी रखने के संबंध में कोई प्रभावी निर्देश पारित नहीं किए।

(76) नियंत्रण बनाए रखने के इरादे का अनुमान केवल क्रम की भाषा से लगाया जा सकता है।इस आशय का न्यायालय का इरादा अभिलेख के सामने स्पष्ट होना चाहिए।न्यायालय की ओर से इस तरह के इरादे को उसके आदेशों में अस्पष्टता के बिना प्रकट किया जाना चाहिए।

(77) इस तरह के इरादे का पता लगाने का एक और तरीका यह देखना है कि मध्यस्थता कार्यवाही के पक्षकारों ने न्यायालय के आदेश को कैसे समझा और उस पर कार्रवाई कैसे की।जहाँ तक भारत संघ का संबंध है, यह उनका विशिष्ट मामला है कि उच्च न्यायालय ने कभी भी मध्यस्थता कार्यवाही पर नियंत्रण नहीं रखा या उसे बनाए रखने का इरादा नहीं रखा।जहाँ तक दावेदार कंपनी का संबंध है, उसने मध्यस्थ की नियुक्ति या रिक्तियों की आपूर्ति और अन्य निर्देशों के लिए निचली अदालत के समक्ष आवेदन भी दायर किए, न कि उच्च न्यायालय के समक्ष।पक्षकारों ने निचली अदालत द्वारा पारित निर्देशों को आगे बढ़ाने के लिए मध्यस्थता कार्यवाही में भाग लिया और उन्होंने विभिन्न अवसरों पर विद्वत निचली अदालत का दरवाजा खटखटाया।दावेदार कंपनी ने पहली बार वर्तमान कार्यवाही (1994 का सिविल पुनरीक्षण संख्या 1685) में उच्च न्यायालय द्वारा मध्यस्थता कार्यवाही पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए एक विशिष्ट अनुरोध के साथ एक आवेदन दायर किया। यह स्वयं दर्शाता है कि 9 जुलाई, 1993 के आदेश को पक्षकारों द्वारा इस आधार पर कभी नहीं समझा गया था या उस पर कार्रवाई नहीं की गई थी कि उच्च न्यायालय ने मध्यस्थता कार्यवाही पर वास्तव में नियंत्रण बनाए रखा था।

(78) हम इस प्रासंगिक तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि उच्च न्यायालय ने स्वयं 1994 के सिविल पुनरीक्षण स न.1685 में पारित अपने 15 दिसंबर, 1995 के आदेश के माध्यम से विद्वत विचारण न्यायालय को उक्त मामले का निपटारा करने का निर्देश दिया था और साथ ही भारत संघ द्वारा दायर आवेदन पर 31 जनवरी, 1996 तक विचार करने के लिए अधिकार क्षेत्र के प्रश्न का भी निर्देश दिया था।विद्वत विचारण न्यायालय ने 8 जनवरी, 1996 के अपने आदेश के माध्यम से इस प्रश्न का निर्णय लिया और अभिनिर्धारित किया कि आवेदन पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र उसके पास है।8 जनवरी, 1996 के आदेश को दावेदार कंपनी द्वारा 1996 के सिविल पुनरीक्षण संख्या 1076 में चुनौती दी गई थी।इससे यह भी पता चलता है कि उच्च न्यायालय का कभी भी मध्यस्थता कार्यवाही पर प्रभावी नियंत्रण रखने का इरादा नहीं था और हमारी राय में, विद्वत विचारण न्यायालय को उचित रूप से स्वतंत्रता प्रदान की गई जहां अधिकार क्षेत्र के प्रश्न का निर्णय करने के लिए विभिन्न आवेदन दायर किए गए थे।न्यायालय का इरादा मध्यस्थता कार्यवाही पर पूर्ण नियंत्रण रखने का होना चाहिए।

(79) उपरोक्त और इस मामले की परिस्थितियों को देखते हुए, हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि उच्च न्यायालय द्वारा 9 जुलाई, 1993 को श्री वाधवा को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने वाले विद्वत विचारण न्यायालय के आदेश की पुष्टि करते हुए समय बढ़ाने के लिए पारित आदेश केवल एक परिणामी आदेश था और यह उच्च न्यायालय द्वारा मध्यस्थता कार्यवाही पर नियंत्रण बनाए रखने के समान आदेश नहीं था।

(80) इस संबंध में कानून के अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों का संदर्भ, विषय को नियंत्रित करना भी फायदेमंद होगा।

(81) मध्य प्रदेश राज्य बनाम मेसर्स सेठ एंड स्केल्टन *(*पी*)* लिमिटेड और अन्य *(16)* के मामले में अपीलार्थी के वकील के इस तर्क को खारिज करते हुए कि पुरस्कार सक्षम अधिकार क्षेत्र के

न्यायालय यानी अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, मंदसौर में दायर किया जाना चाहिए और सर्वोच्च न्यायालय को पहली बार में आपत्तियों पर निर्णय लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया:—

> "श्री श्रॉफ के अनुसार पुरस्कार इस अदालत में नहीं, बल्कि अतिरिक्त अदालत में दायर किया जाना चाहिए था।जिला न्यायाधीश, मंदसौर, वह न्यायालय है जिसके पास संदर्भ के विषय के संबंध में मुकदमे पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र होगा।हम श्री श्रॉफ के इस तर्क को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं।यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि धारा 2 के प्रारंभिक शब्द हैं "इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कुछ भी अप्रिय न हो।"इसलिए, "न्यायालय" अभिव्यक्ति को अधिनियम की धारा 2 (सी) में परिभाषित के रूप में तभी समझना होगा जब विषय या संदर्भ में कुछ भी प्रतिकूल न हो।यह उस प्रकाश में है कि धारा 14 (2) में आने वाली अभिव्यक्ति "न्यायालय"

(16) ए. आई. आर. 1972 एस. सी. 1507-(1972) 3 उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट 233।

अधिनियम को समझना और व्याख्या करनी होगी।यह वही न्यायालय था जिसने 29 जनवरी, 1971 को श्री वी. एस. देसाई को मध्यस्थ के रूप में पक्षों की सहमति से नियुक्त किया था और अपना निर्णय दिया था।यह देखा जाएगा कि उक्त आदेश में आगे कोई निर्देश नहीं दिए गए थे जो यह संकेत देगा कि इस न्यायालय ने पचाट से उत्पन्न होने वाले मामलों से निपटने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र से खुद को अलग नहीं किया था।वास्तव में संकेत इसके विपरीत हैं।29 जनवरी, 1971 के आदेश में निर्देश दिया गया है कि मध्यस्थ को "अपना पुरस्कार देना है।"निश्चित रूप से कानून पुरस्कार दिए जाने के बाद आगे के कदम उठाने पर विचार करता है, और स्वाभाविक रूप से आगे की कार्रवाई करने का मंच केवल यही न्यायालय है।इस आशय का भी निर्देश था कि पक्षकार पुरस्कार देने के लिए समय बढ़ाने के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र हैं। आदेश द्वारा किसी अन्य न्यायालय को ऐसी अधिकारिता के साथ निवेश किए जाने की अनुपस्थिति में, एकमात्र निष्कर्ष जो संभव है वह यह है कि ऐसा अनुरोध केवल उस न्यायालय को किया जाना चाहिए जिसने वह आदेश पारित किया था, अर्थात् यह न्यायालय।

"यह कि इस न्यायालय ने मध्यस्थता कार्यवाही पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखा है, 1 फरवरी, 1971 और 30 अप्रैल, 1971 के अपने आदेशों से स्पष्ट किया गया है।पूर्व तिथि पर, दोनों पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद, इस न्यायालय ने निर्देश दिया कि मध्यस्थता कार्यवाही का रिकॉर्ड बुलाया जाए और एकमात्र मध्यस्थ श्री वी. एस. देसाई को दिया जाए।बाद की तारीख को, फिर से, वकील को सुनने के बाद, इस न्यायालय ने पुरस्कार देने का समय चार महीने के लिए बढ़ा दिया और मध्यस्थ को बॉम्बे में मध्यस्थता कार्यवाही आयोजित करने की अनुमति दी।29 जनवरी 1971 को पारित आदेश की प्रकृति और बाद की कार्यवाही, जो ऊपर निर्दिष्ट की गई है, स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि इस न्यायालय ने मध्यस्थता कार्यवाही पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखा।"

(82) आवेदन के समर्थन में सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न फैसलों पर रिलायंस को रखा गया है।दावेदार कंपनी द्वारा भरोसा किया गया पहला निर्णय मैसर्स गुरु नानक फाउंडेशन बनाम मैसर्स रतन सिंह एंड संस (17) के मामले में है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि उच्चतम न्यायालय स्वयं अधिनियम की धारा 14 के तहत एक निर्णय देने के उद्देश्यों के लिए अनन्य अधिकार क्षेत्र वाला न्यायालय था और यहां तक कि मध्यस्थता कार्यवाही में देरी का संदर्भ देते हुए भी निम्नानुसार देखा गया:—

"अंतहीन, समय लेने वाली, जटिल और महंगी अदालती प्रक्रियाओं ने न्यायविदों को एक वैकल्पिक मंच की खोज करने के लिए प्रेरित किया।

प्रक्रियात्मक उलझनों से बचने के लिए विवादों के समाधान के लिए कम औपचारिक, अधिक प्रभावी और त्वरित और यह उन्हें मध्यस्थता अधिनियम, 1940 (संक्षेप में अधिनियम) की ओर ले गया।हालाँकि, जिस तरह से अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाती है और अदालतों में बिना किसी अपवाद के चुनौती दी जाती है, उससे वकीलों की हँसी उड़ गई है और कानूनी दार्शनिक रो पड़े हैं।अनुभव और कानूनी रिपोर्ट इस बात की पर्याप्त गवाही देते हैं कि अधिनियम के तहत कार्यवाही अत्यधिक तकनीकी हो गई है और हर स्तर पर अनजान लोगों को कानूनी जाल प्रदान करती है।पक्षकारों द्वारा अपने विवादों के शीघ्र निपटारे के लिए चुने गए अनौपचारिक मंच को न्यायालयों के निर्णयों द्वारा अप्रत्याशित जटिलता के 'वैध' का जामा पहनाया गया है।यह मामला काफी हद तक उसी बात को दर्शाता है।

"अधिनियम की धारा 31 उस मंच का प्रावधान करती है जिसमें एक पंचाट दायर किया जा सकता है।धारा 31 की उप-धारा (1) में प्रावधान है कि उस मामले में अधिकारिता रखने वाले किसी भी न्यायालय में एक पंचाट दायर किया जा सकता है जिससे संदर्भ संबंधित है।धारा 31 की उप-धारा (1) में धारा 2 (ग) में उल्लिखित 'न्यायालय' की परिभाषा को शामिल करने का अर्थ होगा कि अधिनिर्णय उस न्यायालय में दायर किया जाना चाहिए जिसमें अधिनिर्णय में शामिल विवाद के संबंध में मुकदमा दायर करने की आवश्यकता होती।यह धारा 14 की उप-धारा (2) में निहित प्रावधान के साथ काफी सुसंगत है।अब तक कोई कठिनाई नहीं है।धारा 31 की उप-धारा (2), (3) और (4) में प्रकट की गई योजना स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि अन्य सभी न्यायालयों को बहिष्कृत करने के लिए केवल एक अदालत को संदर्भ और मध्यस्थता के लिए आकस्मिक कार्यवाहियों से निपटने की अधिकारिता होगी।उप-धारा (3) इस दिशा में स्पष्ट रूप से इंगित करती है जब यह प्रावधान करता है कि मध्यस्थता कार्यवाही के संचालन के संबंध में या ऐसी कार्यवाही से अन्यथा उत्पन्न होने वाले सभी आवेदन उस न्यायालय में किए जाएंगे जहां पुरस्कार दिया गया है या दायर किया जा सकता है और किसी अन्य न्यायालय में नहीं। फिर उप-धारा (4) आती है।यह एक गैर-अस्थाई खंड के साथ खुलता है और चरित्र में व्यापक है।गैर-स्थायी खंड पूरे अधिनियम या तत्काल लागू किसी अन्य कानून में कहीं भी निहित किसी भी चीज़ को बाहर करता है यदि यह उप-धारा (4) में निहित मूल प्रावधान के विपरीत या असंगत है।उस सीमा तक यह न्यायालय की अधिकारिता के सामान्य प्रश्न के लिए एक अपवाद तैयार करता है जिसमें उप-धारा (4) में निर्दिष्ट कार्यवाहियों के संबंध में अधिनियम में प्रदान किए गए अन्य स्थान पर पुरस्कार दायर किया जा सकता है।उप-धारा (4) में निहित प्रावधान का अधिनिर्णय दाखिल करने के संबंध में अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा यदि उसमें निर्धारित शर्तें पूरी हो जाती हैं।अगर ये शर्तें हैं

धारा 14 (2) या धारा 31 (1) में परिकल्पित न्यायालय के अलावा संतुष्ट न्यायालय वह न्यायालय होगा जिसमें अधिनिर्णय दाखिल करना होगा।यह धारा 31 की उप-धारा (4) में गैर-अस्थाई खंड का प्रभाव है।इस प्रकार उप-धारा (4) उस न्यायालय में अनन्य अधिकारिता का निवेश करती है, जिसके लिए किसी भी संदर्भ में एक आवेदन किया गया है और जिसे वह न्यायालय मध्यस्थता कार्यवाही और संदर्भ से उत्पन्न होने वाले सभी बाद के आवेदनों पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालय के रूप में स्वीकार करने के लिए सक्षम है और मध्यस्थता कार्यवाही उस न्यायालय में और किसी अन्य न्यायालय में नहीं की जानी चाहिए।इस प्रकार उप-धारा (4) न केवल उस न्यायालय को अनन्य अधिकारिता प्रदान करती है जिसके लिए किसी भी संदर्भ में आवेदन किया जाता है, बल्कि साथ ही किसी अन्य न्यायालय की अधिकारिता को भी हटा देती है, जिसकी इस संबंध में अधिकारिता भी हो सकती है।इस बात को स्पष्ट करने के लिए, यदि किसी विशेष न्यायालय में धारा 31 (1) के साथ पठित धारा 14 (2) के तहत एक पुरस्कार दायर करने की आवश्यकता थी, क्योंकि

वह न्यायालय जिसमें पुरस्कार के विषय-वस्तु को छूते हुए एक मुकदमा दायर करने की आवश्यकता होती, लेकिन यदि अधिनियम के तहत संदर्भ में कोई आवेदन किसी अन्य न्यायालय में दायर किया गया है जो उस आवेदन को स्वीकार करने के लिए सक्षम था, तो पहले उल्लिखित न्यायालय के अपवर्जन के लिए, धारा 31 (4) में निहित प्रावधान के प्रबल प्रभाव को देखते हुए, केवल बाद वाले न्यायालय के पास पुरस्कार प्राप्त करने का अधिकार क्षेत्र होगा और पुरस्कार को अकेले उस न्यायालय में दायर करना होगा और किसी अन्य न्यायालय के पास इसे स्वीकार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।"

"दिलचस्प बात यह है कि इस न्यायालय के एक अधिकारी ने मध्यस्थ को अदालत का कोई निर्देश प्राप्त किए बिना दिल्ली उच्च न्यायालय में पुरस्कार दायर करने की सलाह दी।हमें इस न्यायालय के एक अधिकारी द्वारा प्रथम न्यायालय की अधिकारिता के इस दुरूपयोग के बारे में अपनी अप्रसन्नता दर्ज करनी चाहिए।हम और नहीं कहते हैं।इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस न्यायालय द्वारा तीसरे प्रत्यर्थी को एक संदर्भ दिया गया था और इस न्यायालय ने मध्यस्थता कार्यवाही के संचालन के तरीके और विधि के बारे में आगे निर्देश दिया और मध्यस्थता कार्यवाही को पूरा करने के लिए समय निर्धारित किया, अकेले इस न्यायालय के पास पुरस्कार को स्वीकार करने का अधिकार क्षेत्र होगा।"

"श्री नरूला ने अंत में आग्रह किया कि यदि यह न्यायालय धारा 31 की उप-धारा (4) को लागू करके अपने अधिकार क्षेत्र को कम करता है, जैसा कि प्रथम प्रतिवादी की ओर से प्रचार किया गया है, तो यह अपीलार्थी को लेटर पेटेंट के तहत अपील करने के अपने मूल्यवान अधिकार से वंचित कर देगा और संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगा।यदि इस न्यायालय के पास पुरस्कार पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है और धारा 31 (4) को देखते हुए अकेले इस न्यायालय के पास पुरस्कार पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है

इसका अर्थ है कि पुरस्कार अकेले इस न्यायालय में दायर किया जाना है और कोई अन्य नहीं, इसे एक विशिष्ट याचिका द्वारा पराजित नहीं किया जा सकता है कि अपील के अधिकार से इनकार किया जाएगा।मैसर्स सेठ स्केल्टन (पी) लिमिटेड मामले में एक समान स्थिति में, इस न्यायालय ने निर्णय दिया कि पुरस्कार अकेले इस न्यायालय में दायर किया जाना चाहिए जो निश्चित रूप से अपील करने के अवसर को नकार देगा क्योंकि यह अंतिम न्यायालय है।इस न्यायालय द्वारा गरिकापट्टल वीराया बनाम एन. सुब्बैया चौधरी मामले में जैसा कि अभिनिर्धारित किया गया है, यह स्वीकार करते हुए कि अपील का अधिकार एक निहित अधिकार है और उच्चतर न्यायालय में प्रवेश करने का ऐसा अधिकार वादी को प्राप्त होता है और उस तारीख से और उस तारीख से मौजूद है जब हम इस तरह का अधिकार ले रहे हैं, इस दृष्टिकोण से इनकार या पराजित नहीं किया जाता है क्योंकि उच्चतम न्यायालय जिसमें कोई व्यक्ति अपील के माध्यम से शामिल हो सकता है, उन सभी दलीलों को स्वीकार करेगा जिन्हें अपीलार्थी की ओर से प्रचार करना पड़ सकता है।अपीलार्थी के लिए इस न्यायालय का द्वार बंद नहीं किया जा रहा है।वास्तव में उसके लिए दरवाजे को पूरी तरह से खुला रखा जा रहा है ताकि वह उन सभी विवादों को उठा सके जिन्हें एक प्रारंभिक समन में कार्यवाही में उठाया जा सकता है।इसलिए, हम इस विवाद में कोई योग्यता नहीं देखते हैं और इसे खारिज किया जाना चाहिए।"

(83) उपरोक्त सिद्धांत का पालन भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पी. एम. पॉल बनाम भारत संघ (18) पोर्ट ऑफ़ मद्रास बनाम इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के न्यासी (19); ठाकुर दास और अन्य बनाम श्रीमती। विद्यावती और अन्य *(20)*, पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य बनाम लुधियाना स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड *(21)* और राजकोट के वैद्य हरिशंकर

लक्ष्मीराम राज्यगुरु बनाम राजकोट के प्रतापराय हरिशंकर राज्यगुरु *(22)*।

(84) उपरोक्त निर्णयों के प्रासंगिक उद्धरणों को नंगे पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि मैसर्स सेठ एंड स्केल्टन (पी) लिमिटेड और मैसर्स गुरु नानक फाउंडेशन के मामलों में प्रतिपादित सिद्धांतों का उच्चतम न्यायालय ने बाद के सभी मामलों में पालन किया।एक अन्य सामान्य विशेषता यह है कि इनमें से अधिकांश मामलों में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं या तो पक्षों की सहमति से या उनके अधिपतियों द्वारा नियुक्त मध्यस्थ को हटाने पर एक मध्यस्थ नियुक्त किया था। मध्यस्थता कार्यवाही के संचालन और यहां तक कि निर्णय दाखिल करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशिष्ट निर्देश दिए गए थे।निश्चित रूप से देरी को प्रासंगिक विचार माना जाता था लेकिन अपने आप में देरी

(18) 1989 सप्लीमेंट (एल) एससीसी 368
(19) 1995 (5) एस. सी. सी. 531
(20) 1987 (सप.) एससीसी 154
(21) 1993 (1) एससीसी 205
(22) 1988 (3) एससीसी 21

(23) निचली अदालत से उच्च न्यायालय द्वारा मध्यस्थता कार्यवाही पर प्रभावी नियंत्रण के प्रतिधारण या धारणा को उचित ठहराने के लिए उपरोक्त निर्णयों में उनके प्रभुत्त्वों द्वारा इंगित किया गया पर्याप्त आधार नहीं हो सकता है, जहां मामला काफी अवधि से लंबित था।सामान्य सिद्धांत जो उभरता है वह यह है कि कानून के सामान्य पाठ्यक्रम में निर्धारित पदानुक्रम में उच्च न्यायालयों को अपने आदेशों में उचित अभिव्यक्ति द्वारा मध्यस्थता कार्यवाही पर विशिष्ट नियंत्रण रखने के अपने इरादे को स्पष्ट करना चाहिए।अन्यथा, कार्यवाहियों पर नियंत्रण आम तौर पर सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय पर छोड़ दिया जाना चाहिए, जहां अपने सामान्य पाठ्यक्रम में कार्यवाहियों को विवाद पर निर्णय लेने के लिए सक्षम निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में स्थापित किया जाना चाहिए और किया जाना चाहिए।

85) अब हम दावेदार कंपनी (सिविल मिस्क) की ओर से की गई वैकल्पिक प्रार्थना पर चर्चा करने के लिए आगे बढ़ेंगे।1994 के सिविल पुनरीक्षण सं. 1685 में 1995 का सं. 6362) अनुरोध करता है कि निर्णय देने के लिए समय को महीनों तक बढ़ाया जाए और इस न्यायालय को मध्यस्थता कार्यवाही पर प्रभावी नियंत्रण रखना चाहिए।याचिकाकर्ता के अनुसार कार्यवाही के समापन में अत्यधिक देरी, जिसके परिणामस्वरूप उसे इस तरह की अत्यधिक देरी का सामना करना पड़ा और मध्यस्थता कार्यवाही के सुचारू और त्वरित निष्कर्ष में बाधा डालने में प्रतिवादीगण द्वारा अपनाया गया रवैया इस तरह के आदेश को पारित करने को उचित ठहराएगा।दूसरी ओर, भारत संघ की ओर से उपस्थित विद्वान वकील का तर्क है कि न्यायालय आम तौर पर मध्यस्थता कार्यवाही पर नियंत्रण तब तक नहीं रखेगा जब तक कि वह स्वयं एक मध्यस्थ की नियुक्ति नहीं करता है और इसके अलावा कुछ मजबूर करने वाली परिस्थितियों को रिकॉर्ड पर रखा जाता है ताकि उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रभावी और पूर्ण नियंत्रण को उचित ठहराया जा सके

(1) 86) मामले के तथ्यों से यह स्पष्ट है कि किसी भी समय उच्च न्यायालय ने अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करते हुए कभी भी किसी मध्यस्थ को नियुक्त नहीं किया था या मध्यस्थता कार्यवाही को आगे बढ़ाने में प्रगति के संबंध में भौतिक परिणाम का प्रभावी निर्देश नहीं दिया था।इसके विपरीत, उच्च न्यायालय ने समय-समय पर केवल विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की थी और अभिलेख स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विचारण न्यायालय ने कार्यवाही पर प्रभावी और पूर्ण नियंत्रण का प्रयोग किया था।

87) जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, दावेदार कंपनी के साथ-साथ भारत संघ द्वारा दायर किए गए सभी तीन आवेदन निचली अदालत के समक्ष दायर किए गए थे और उस अदालत द्वारा

निर्णय लिया गया था।पक्षकारों ने ऐसे आदेशों पर कार्रवाई की और इस न्यायालय के समक्ष दायर संशोधनों को खारिज कर दिया गया (1991 का सिविल पुनरीक्षण संख्या 1220,1991 का 1221 और 1991 का 1245) और उन आदेशों को अंतिम रूप भी मिल गया था।

(88) दोहरी शर्तें जो उच्च न्यायालय को किसी उपयुक्त मामले में मध्यस्थता कार्यवाही पर प्रभावी और पूर्ण नियंत्रण रखने के लिए राजी कर सकती हैं, सामान्य रूप से इस प्रकार होंगी:-

(a) मध्यस्थ की नियुक्ति पक्षकारों की सहमति पर या अन्यथा उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है।

(b) न्यायालय के समक्ष अपनी अपीलीय या पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए विशिष्ट और बाध्यकारी परिस्थितियाँ हैं, उस स्थिति में न्यायालय के इरादे को प्रभावी निर्देश पारित करके, उस न्यायालय द्वारा मध्यस्थता कार्यवाही पर पूर्ण और प्रभावी नियंत्रण के प्रयोग को उचित ठहराते हुए, न्यायालय के आदेशों में खुद को प्रकट करना चाहिए।

(89) मैसर्स गुरु नानक फाउंडेशन, मैसर्स सेठ एंड स्केल्टन (पी) लिमिटेड और पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के मामलों सहित दावेदार कंपनी द्वारा भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सभी पूर्व-नोटिस किए गए निर्णयों पर भरोसा किया गया, वे मामले हैं जहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं मध्यस्थों (भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों) की नियुक्ति की थी और मध्यस्थता कार्यवाही की प्रगति और नियंत्रण के लिए प्रभावी निर्देश पारित किए थे और यहां तक कि पंचाट को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर करने का निर्देश भी दिया था।इस उद्देश्य के लिए हम यह भी देख सकते हैं कि अकेले भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास ऐसे आदेश देने की प्रबल शक्ति है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामले में "पूर्ण न्याय" करने के लिए आवश्यक हो।

(90) पूर्व में ध्यान दिए गए मामलों में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष रूप से ध्यान दिया कि मध्यस्थता की कार्यवाही पर न्यायालय का नियंत्रण था, जो निश्चित रूप से यहां मामला नहीं है।हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि पिछली कार्यवाही में उच्च न्यायालय का कोई भी आदेश हमारे ध्यान में नहीं लाया गया है जो दूर से भी यह सुझाव दे सकता है कि उच्च न्यायालय मध्यस्थता कार्यवाही पर नियंत्रण रखने का इरादा रखता है।दूसरी ओर, उच्च न्यायालय और यहां तक कि उच्चतम न्यायालय के उनके अधिपतियों ने मामले के तथ्यों के बावजूद स्पष्ट रूप से संकेत दिया है कि मामले को अपने सामान्य कानूनी पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए।हम इस मामले में इसके विपरीत कोई अपवाद बनाने के लिए कोई असाधारण परिस्थितियाँ नहीं देखते हैं।

(91) इसमें कोई संदेह नहीं है कि मध्यस्थता कार्यवाही की प्रगति और समापन में देरी होती है, लेकिन प्रत्येक पक्ष इसके लिए दूसरे को दोषी ठहराता है।हालाँकि, अब पंचाट 27 अगस्त, 1996 को दिया गया है और यहां तक कि पंचाट पर आपत्तियाँ भी भारत संघ द्वारा दायर की गई हैं, जिन पर सक्षम न्यायालय द्वारा प्राप्ति पर और कानून के अनुसार विचार किया जाएगा।हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि मुकदमा

सक्षम क्षेत्राधिकार वाला न्यायालय होने के कारण न्यायालय ने मध्यस्थों की नियुक्ति की थी।इसके अलावा, इन कार्यवाहियों में से किसी भी पक्ष को कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा यदि विद्वत विचारण न्यायालय को मूल अधिकार क्षेत्र का न्यायालय होने के नाते कानून के अनुसार मामलों पर नियंत्रण रखने और उनसे निपटने की अनुमति दी जाती है, जो कि निश्चित रूप से एक बहुत व्यापक अधिकार क्षेत्र है।

(92) मध्यस्थता अधिनियम की धारा 39 के प्रावधानों के तहत, किसी पंचाट को रद्द करने या अस्वीकार करने के आदेश के खिलाफ अपील की जा सकती है।इस न्यायालय के लिए अपने पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए मध्यस्थता कार्यवाही पर प्रभावी और पूर्ण नियंत्रण ग्रहण करने के लिए, पक्षकारों को अपील के अधिकार से वंचित कर देगा जो विशेष रूप से अधिनियम के प्रावधानों के तहत उन्हें दिया गया है। हम कोई कारण नहीं देखते हैं कि हमें अधिनियम के प्रावधानों के तहत पार्टियों को उनके लिए उपलब्ध इस वैधानिक अधिकार से वंचित करना चाहिए, जिसे वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में शायद ही उचित ठहराया जा सकता है।

(93) जिन मामलों पर पहले ध्यान दिया गया था, उनमें भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन मामलों के तथ्यों में पूर्ण न्याय करने के इरादे से भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत निहित व्यापक शक्तियों की सहायता से अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया और पक्षों के बीच विवाद का न्यायनिर्णयन करने के लिए स्वयं मध्यस्थ नियुक्त किया था।किसी अन्य न्यायालय को ऐसी शक्तियाँ नहीं दी गई हैं।मूल अंतर संविधान के अनुच्छेद 142 के साथ पठित अनुच्छेद 136 के तहत भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विशेष अपीलीय शक्तियों के विपरीत उक्त न्यायालयों द्वारा प्रयोग की जाने वाली सामान्य दीवानी अपीलीय शक्ति के बीच है।साधारण अपीलीय या पुनरीक्षण अधिकारिता के प्रयोग में न्यायालय को ऐसी शक्ति के प्रयोग को नियंत्रित करने वाले स्वीकृत मानदंडों के भीतर आदेश पारित करने होते हैं।

1996 का सिविल पुनरीक्षण सं. 1076:—

(94) उपरोक्त संशोधन (1994 का सं. 1685) में शामिल विभिन्न विवादों पर विस्तार से दलीलें सुनने के दौरान हमारे ध्यान में लाया गया कि इस दीवानी पुनरीक्षण पर सुनवाई की जानी चाहिए ताकि इस मुद्दे में विवाद को अंततः निर्धारित किया जा सके।इस पुनरीक्षण में याचिकाकर्ता एच. एस. तुली (मेसर्स) और सन्स बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड ने विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा क्रमशः 8 जनवरी, 1996 और 27 जनवरी, 1996 को पारित दो आदेशों को चुनौती दी है।

मध्यस्थ के समक्ष लंबित मध्यस्थता कार्यवाही।निचली अदालत ने 29 नवंबर, 1995 को मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही पर एकतरफा रोक लगा दी थी।इस क्रम में।विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा यह भी कहा गया कि पंचांट प्रकाशित करने के लिए समय बढ़ाने के लिए मध्यस्थता अधिनियम की धारा 28 के तहत एक आवेदन उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित था और यह उचित माना गया कि उच्च न्यायालय को मामले के उस पहलू से निपटना चाहिए।

(95) शुरुआत में हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जब निचली अदालत ने उपरोक्त आदेश पारित किए, तो सिविल पुनरीक्षण संख्या 1685 में अंतिम आदेश के साथ-साथ मध्यस्थ द्वारा पंचाट देने के लिए समय बढ़ाने का निर्णय उच्च न्यायालय ने अपने 4 जुलाई, 1995 और 7 सितंबर, 1995 के आदेशों के अनुसार लिया था।जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है कि भारत संघ द्वारा उच्च न्यायालय के इन आदेशों के खिलाफ विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की गई थीं, जिन्हें माननीय सर्वोच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा सुनने का आदेश ;-अपने आदेश, दिनांक 12 अगस्त, *1997* के माध्यम से दिया गया है। इस पुनरीक्षण में उठाया गया प्रारंभिक प्रश्न यह है कि क्या विद्वत विचारण न्यायालय को 8 जनवरी, 1996 का आदेश पारित करने में न्यायसंगत ठहराया गया था, जिसमें कहा गया था कि उसे अधिनियम की धारा 5 और 11 के तहत भारत संघ द्वारा दायर याचिका पर विचार करने और निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र था। यह याचिका अभी भी विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित है।हालाँकि, इस बीच, मध्यस्थ के समक्ष मध्यस्थता कार्यवाही की प्रगति के खिलाफ रोक को खाली कर दिया गया था, इसलिए मध्यस्थ ने पहले ही निर्णय घोषित कर दिया था।विद्वत विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कि उसके पास याचिका पर विचार करने और निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र है, मुख्य रूप से अधिनियम की धारा 31 (4) के प्रावधानों पर भरोसा रखा। विवादित फैसले का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार है:

> "जहाँ पहला आवेदन निर्विवाद रूप से मूल न्यायालय में दायर किया गया कहा जा सकता है, वहाँ उच्च न्यायालय में कोई आवेदन दायर नहीं किया जाता है।उच्च न्यायालय अपील या पुनरीक्षण में मामले पर विचार कर रहा है न कि मूल कार्यवाही के माध्यम से।यह आगे निर्धारित किया गया है कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा 4 में अनुध्यात अधिकारिता विचारण न्यायालय की अधिकारिता है।बाद के मामले के कानून में, यह निर्धारित किया गया है कि जब किसी संदर्भ से संबंधित मध्यस्थता अधिनियम के तहत किसी आवेदन पर कुछ कार्यवाही किसी विशेष न्यायालय में की गई है।, तब अकेले उस न्यायालय को मध्यस्थता अधिनियम की धारा 31 (4) के तहत उस संदर्भ से उत्पन्न होने वाले बाद के आवेदनों पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र होना चाहिए। इसके अलावा, यह भी ध्यान देने योग्य है कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 28 के तहत समय बढ़ाने के लिए आवेदन 4 दिसंबर, 1995 को माननीय उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है और जबकि तत्काल आवेदन

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 5 के तहत 27 नवंबर, 1995 को दायर किया गया है और इसलिए यह मध्यस्थता अधिनियम की धारा 28 के तहत उपरोक्त आवेदन से पहले है।

(96) श्री तुली ने तर्क दिया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को ध्यान में रखते हुए यह न्यायालय इस आवेदन पर निर्णय लेने के लिए सशक्त सक्षम अधिकार क्षेत्र का एकमात्र न्यायालय है।

(97) हम पहले ही, इस याचिका के पक्षकारों द्वारा उठाए गए विभिन्न तर्कों पर बहुत विस्तार से चर्चा कर चुके हैं,अधिनियम की धारा 31(4)के साथ पठित धारा 2(c)और सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 15 की व्याख्या करते हुए इस प्रश्न का उतर दिया है कि कौन सा न्यायालय सक्षम अधिकार क्षेत्र का न्यायालय है, विद्वत विचारण न्यायालय निम्नतम श्रेणी का न्यायालय होने के नाते, याचिका पर विचार करने और निर्णय लेने के लिए सक्षम न्यायालय है।हम 8 जनवरी, 1996 के विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं देखते हैं।27 जनवरी, 1996 का आदेश, किसी भी मामले में, किसी भी हस्तक्षेप का आह्वान नहीं करता है क्योंकि मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही के संबंध में रोक हटाने का आदेश समाप्त हो गया था और मध्यस्थ ने अदालत में पंचाट दायर किया था। इसलिए, हमें इस पुनरीक्षण याचिका को खारिज करने में कोई संकोच नहीं है।तथापि, हम न्याय के हित में उन मुख्य कार्यवाहियों के संबंध में अलग-अलग निर्देश पारित करेंगे जो अभी भी लंबित हैं (अधिनियम की धारा 5 और 11 के तहत), जिनमें से वर्तमान पुनरीक्षण उत्पन्न होता है।

निष्कर्ष:—

(98) इसलिए, हमारे लिए यह अनिवार्य है कि हम इस न्यायालय में लंबित कार्यवाही को जारी रखने और समाप्त करने के संबंध में कुछ निर्देश जारी करें।भारत संघ द्वारा 1994 के सिविल पुनरीक्षण सं. 1685 और 1995 के समीक्षा आवेदन सं. 34 को खारिज कर दिया गया है।हमारा विचार है कि विद्वत विचारण न्यायालय मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए दावेदार कंपनी द्वारा दायर किए गए आवेदन पर विचार करने के लिए सक्षम था।इसके अलावा, हम श्री ओ. पी. गुप्ता को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने वाले विवादित आदेश में अधिकार क्षेत्र की कोई त्रुटि नहीं देखते हैं।

(99) हम पहले ही मान चुके हैं कि वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में सक्षम अधिकार क्षेत्र का न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय है।इस प्रकार, इसके लिए एक आवश्यक परिणाम के रूप में, 8 जनवरी, 1996 के न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाले सिविल पुनरीक्षण संख्या 1076 का 1996 को भी खारिज कर दिया जाता है।भारत संघ द्वारा दायर अधिनियम की धारा 5 और 11 के तहत एक याचिका अभी भी विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित है, हालांकि एकमात्र मध्यस्थ श्री ओ. पी. गुप्ता के समक्ष मध्यस्थता की कार्यवाही पहले ही समाप्त हो चुकी है और न्यायालय में पंचाट दायर किया गया है।विद्वत विचारण न्यायालय सक्षम अधिकारिता का न्यायालय होने के कारण, हमारा मानना है कि पंचाट विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष दायर किया जाना चाहिए था,

जिसने शुरू में श्री गुप्ता को मध्यस्थ नियुक्त किया था।इसलिए हम निर्देश देंगे कि इस न्यायालय की रजिस्ट्री में दाखिल किए गए निर्णय के साथ-साथ निचली अदालत के रिकॉर्ड, यदि कोई हों, को सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय, यानी सिविल जज (जूनियर डिवीजन), चंडीगढ़ को तुरंत प्रेषित किया जाएगा।मध्यस्थ को हटाने के लिए भारत संघ द्वारा दायर याचिका की सुनवाई उसी न्यायालय द्वारा की जाएगी, जो भारत संघ द्वारा पंचाट पर दायर आपत्तियों का भी निपटारा करेगा।दूसरे शब्दों में, अधिनियम की धारा 5 और 11 के तहत भारत संघ की याचिका और न्यायालय के पंचाट नियम बनाने के लिए दायर की गई उसकी आपत्तियों की सुनवाई और निर्णय विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा एक साथ किया जाएगा।पक्षकारों को 7 फरवरी, 2000 को विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

(100) उपरोक्त आदेशों और निर्देशों के परिणामस्वरूप, हमें सिविल विविध 1995 का स 13460 और सिविल विविध 1996 का स 7375 पर एक परिणामी आदेश पारित करना होगा दोनों अधिनियम की धारा 28 के तहत, समय बढ़ाने का अनुरोध करते है। इस पूर्वावलोकन में देखते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा समय बढ़ाया गया था-अपने 9 जुलाई, 1993 के आदेशों के अनुसार (सी. आर. नं. 1245/91), 14 मार्च, 1996 और 16 जुलाई, 1996 ने मध्यस्थ को पंचाट बनाने और प्रकाशित करने की अनुमति दी।इसके परिणामस्वरूप, न्यायालय में पंचाट पहले ही दायर किया जा चुका है। हम आवेदक द्वारा अनुरोध किए गए समय के विस्तार को अस्वीकार करने या 9 जुलाई, 1993,14 मार्च, 1996 और 16 जुलाई, 1996 के आदेशों को वापस लेने का कोई वैध कारण नहीं देखते हैं। हमारा विचार है कि इस आधार पर पिछले छह वर्षों में हुई मध्यस्थता कार्यवाही को समाप्त करना न्याय के हित में नहीं होगा।

(101) हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि हम श्री गुप्ता की मध्यस्थ के रूप में नियुक्ति तक सीमित निचली अदालत के आदेश की पुष्टि कर रहे हैं।पंचांट के साथ-साथ श्री गुप्ता के पूर्वाग्रह, आचरण या अन्यथा के लिए भारत संघ की आपत्तियाँ की सुनवाई की जाएगी और सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय द्वारा लंबित याचिकाओं में निर्णय लिया जाएगा।

(102) कार्यवाही के प्रति किसी भी पक्ष द्वारा अपनाए गए कठोर रवैये के परिणामस्वरूप हुई असाधारण देरी को ध्यान में रखते हुए, हम विद्वत निचली अदालत से अनुरोध करेंगे कि इस फैसले की एक प्रति निचली अदालत के रिकॉर्ड में रखे जाने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर शेष याचिकाओं का निपटारा किया जाए।हम इस पवित्र आशा को व्यक्त करते हैं कि दोनों पक्ष निचली अदालत के समक्ष सहयोग करेंगे और वे कार्यवाही के प्रत्येक चरण पर तुच्छ आपत्तियां उठाने के बजाय अपने वास्तविक विवादों के अंतिम निर्धारण का रवैया अपनाएंगे।हमें यकीन है कि विद्वत विचारण न्यायालय अंततः पूर्व-निर्देशित समय के भीतर और कानून के अनुसार मामले का निपटारा करने में सक्षम होगा।कोई पार्टी बहुत असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी स्थगन की हकदार नहीं होगा।

(103) दोनों पुनरीक्षण याचिका का निपटारा करते है। हालाँकि, मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, हम पक्षों को उनकी अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ देते हैं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य

के लिए उपयुक्त रहेगा ।

जसप्रीत कौर
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
हिसार, हरियाणा